[श्री रामचन्द्र विकल]

हैं और न कोई कारखानें हैं, और गाजियाबाद में तो मैं जानता हूं कि 20 साल से जमीन लो हुई पड़ो है । लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधान मंत्री थे । उन्होंने आदेश दे दिया था कि जो जमीन किसान को खाली पड़ी है वह उस को लौटा दी जाय । वह उस पर खेती करे और जब उस की जरूरत हो तो वह ले ली जाय । आज इस से देश का बड़ा राष्ट्रीय अहित हो रहा है । शहरों के बढ़ते हुए आकार के लिये जमीन को पहले से एक्वायर कर लिया गया है और बहुत से लोग तो वहां जनीन का व्यापार कर रहे हैं । पहले जमीन ले लेते हैं और किसान का जो मुआवजा है उस से 50 गुना कीमत उस की वसूल करते हैं । तो किसान को इस तबाही से बचाने के लिये इसी सत्र में भूमि अधिग्रहण कानून आप पास करें । यही आप से कहना चाहता हूं ।

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF INDUSTRY

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI); Now, we take up dis cussion on the working of the Ministry of Industry *(Interruptions)*

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Sir, I am on a point of order. I want to mention that today's Calling Attention was not expected to come up today and it took a long time. And now only we are starting the discussidn on the working of the Ministry of Industry. It is very seldom that we get an opportunity to discuss this Mini stry. And one full day is reserved for the discussion. If we start the discussion now, it will go up to 9 0 clock. Therefore, I request you to allow the discussion upto 6 O' clock and the rest We can continue tomorrow so that a full-fledged discussion can take place and a number of speaker? can participate.

संसदीय कार्य विभाग मे राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) · उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है तो आप इस बहस को 6 बजे के बदने 8 बजे तक चला लीजिए, लकिन आज इस को खत्म करना है क्योंकि कल बहुत सा बिजनेस है और उस सब को खत्म करना है ।

SHRI SURESH KALMADI (Maharashtra); Sir I would like to say that the discussion on this Ministry of Industry is a very important discussion. And the House has to discuss it threadbare. I therefore suggest that the Rajya Sabha may meet for one more day on the 11th and take up this discussion for the full day.

श्री कल्पनाथ राय · इस को आप 8 बजे तक ले चलिये ।

श्री सुशील चन्द महन्त (हरियाणा) · मेरी एक प्रार्थना है कि इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री का जो डिस्कशन है वह इतना वास्ट है कि उस में बहुत सी बातें आ जाती हैं । 1947 से, जब से हम को आजादी मिली उस के बाद से आज तक जो देश की दुर्दशा हो रही है. . . .

SHRI J. K. JAIN (Madhya Pradesh): Sir, is he on a point of order or he has started the debate?

श्री सुशील चन्द महन्त : और आज जो हालत है देश की वह इस इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की वर्किंग के कारण है । मैं यह कहूंगा कि इस के लिये वक्त अधिक नहीं है । इस के डाइरेक्शन फाल्टी हैं और प्रायरिटीज ठीक नही हैं (व्यवधान)

SHRI SURESH KALMADI; There should be a full-fledged discussion. ■ -

श्री सुशील चन्द महन्त · इस देश को करीबन सब प्राथमिकतायें इस के डिस्कशन में सामने आ जायेंगी और

इतने छोटे से अरसे में इस को रोक कर रखा जाय और बहस के लिये अधिक समय न दिया जाय तो यह बहुत अन्याय होगा ।

श्री कल्पनाथ राय : यहां सदन के सभी सदस्य मौजूद हैं विरोधी पक्ष के भी और सत्ता पक्ष के भी । आप इस पर जितने घंटे चाहें बहस कीजिए, इस में हम को एतराज नहीं है । लेकिन अच्छा होगा कि आप इस को आज खत्म कर दें, 8 बजे तक, 9 बजे तक या 10 बजे तक आप बैठिये और बहस कीजिए ।

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, it was decided that a full day will be allotted to discuss the functioning of the Ministry of Industry. Since the Calling Attention and the other things had taken so much time, only at 5 minutes to 4 o'clock we. are taking this up. The question is whether we can continue the discussion beyond 6 o'clock. Our suggestion is that let the discussion continue upto 6 o'clock and then let it be continued tomorrow. There should be no harm if we continue this tomorrow. There will be no Calling Attention tomorrow. so we can continue it tomorrow. After 6 o'clock we adjourn and continue! the discussion tomorrow.

SHRI LAL K. ADVANI (Madhya Pradesh) Sir, I am happy that the Leader of the House is also here. In a situation of this kind. I am sure, he will be responsive. We know that tomorrow and the day after we have some legislative business, which Government would naturally like to be concluded. On behalf of the Opposition, I can say that we will see to it that all the legislative business is completed before we adjourn *sine die* day after tomorrow. In any case, we can sit late day after tomorrow and complete the legislative business. But so far the discussion on the Ministry of Industry is concerned, it will be appreciated that it will be in the fitness of things to give adequate time to it for discussion, meaning that we should continue discussion on it tomorrow also after discussing it till six o'clock today. Continuing the debate after six o'clock has its own implications.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): It was your suggestion that alt the legislative business will be over by Thursday, I have no objection. But in that case we may have to sit late in the evening tomorrow and day after also because the business which we are having we will have to transact it. Tomorrow there will be no calling attention and day after tomorrow also there will be no calling attention. Otherwise it will be a problem. If you agree I think we can carry on till such time as we want today and the rest can be done tomorrow. But it is on the under standing that all the legislative business will be completed by Thursday.

SOME HON. MEMBERS; Yes, ye*. In any case we will be having no calling attention tomorrow and day after.

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली) : डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं मैम्बर साहबान से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि बिजिनैस ऐडवाइजरी कमेटी ने जो टाइम अलाट किया है, उसको कीप-अप करें, एकाध मिनट इधर-उधर हो सकता है । लम्बे भाषण करेंगे तो 5–10 घंटे क्या दो दिन में भी बहस पूरी नहीं हो सकती । श्री यादव, आपके 5 मिनट हैं ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग के कार्यकरण पर चर्चा आरंभ करने का अवसर मुझे आपने दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्रीमन्, इस पर चर्चा करने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़े समय में बातें कही नहीं जा सकतीं पूरी, फिर भी इस पर चर्चा आरंभ

[श्री रामदेव नारायण यादव]

करने से पहले मैं गांधी जी के कुछ शब्दों को रखना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी बातें प्रारंभ करूंगा ।

श्रीमन्, गांधी जी के शब्दों को इसलिए रखना चाहूंगा कि भारत की जो अर्थ-व्यवस्था थी उसके अनुसार जो यहां पर औद्योगिक व्यवस्था हम कायम करना चाहते थे, उसका आधार गांधीवादी दर्शन ही मानकर चले थे हालांकि गांधीवादी दर्शन केवल नारे के लिए रह गया है, काम के लिए नहीं रह गया है । हम चाहते हैं कि गांधी जी का जो दर्शन था उसके आधार पर अपने उद्योगों की स्थापना की जाए, उस दिशा को केवल लिए जाए जिसके कारण हमारे देश का जो विनाश हुआ है, वह विनाश आगे न हो तथा देश की गाड़ी सही पटरी पर चले । गांधी जी ने कहा था कि जब तक हाथ को हम प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक देश नहीं बनेगा । भारत के अन्दर भूमि, पूंजी, आदमी और व्यवस्था को अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो पता चलेगा कि हमारे पास प्रति व्यक्ति जमीन कम है, प्रति व्यक्ति पूंजी कम है और आदमी ज्यादा हैं । जमीन कम, पूंजी कम और आदमी ज्यादा । इसलिए उद्योग ऐसे बनाने चाहिए जो कम से कम जमीन पर, कम से कम पूंजी में ज्यादा से ज्यादा हाथों को काम दे सकें । यह हमारी दृष्टि होनी चाहिए जो गांधी जी की दृष्टि थी । लेकिन हमारी दृष्टि बदल गई । हमने प्रारंभ किया ज्यादा से ज्यादा जमीन पर, ज्यादा से ज्यादा पूंजी लगाकर ऐसे उद्योग खड़े किए जिसमें कम से कम हाथों को काम मिला और कम से कम हाथों को काम मिलने लगा तो लोग बेरोजगार होते चले गए । हां उद्योगों की स्थापना से लोगों को रोजगार देने का प्रश्न था, हां इन बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना से लोग बेरोजगार होते चले गए और हम उसको आज तक सुधार नहीं पाए हैं । अगर हमें यह देखना है तो जो रमेशचन्द्र दत्ता की 'इकानामिक हिस्ट्री आफ इंडिया' में उन्होंने लिखा है उसको पढ़ें । उन्होंने इसमें लिखा है कि अंग्रेजों के द्वारा भारत के ग्रामीण उद्योगों को नष्ट करने की जो योजना बनाई गई, आजादी के बाद भी जब अपने देश की सरकार बनी उस सरकार ने भी इसी अंग्रेजों की बनाई हुई नीति को चलाया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया । उसकी भी नीति यही रही । गांधी जी का चर्खा एक प्रतीक था । प्रतीक का मतलब है कि वह हाथ का प्रतीक काम का प्रतीक, छोटे उद्योगों का प्रतीक था । घर घर में अगर चर्खा चलेगा तो छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना होगी जिससे लोगों को रोजी रोटी मिलती रहेगी, आर्थिक साधन गांवों में, झोंपड़ियों में भी लोगों को मिलेंगे । लेकिन हम उसको भूल गये, हमने उसमें परिवर्तन कर दिया । इसलिये गांधी जी के बारे में कहा जाता था कि गांधी जी बड़ी मशीनरी के विरुद्ध हैं और गांधी जी के दर्शन के बारे में कहा जाता था और आज अगर उसी नीति को लेकर माननीय चौधरी चरण सिंह कह दें तो उनको भी आज के आधुनिक युग के विद्वान लोग कहते हैं कि यह 16 वीं, 14 वीं शताब्दी की, बैलगाड़ी की बात करते हैं, उस युग की बात करते हैं । गांधी जी ने कहा था कि "मुझे जिस पर आपत्ति है वह मशीनरी की झक है । मुझे मशीनरी के प्रति कोई आपत्ति नहीं है । झक ही है कि वे मशीनरी को श्रम बचाने वाला मानते हैं । यह कहां तक ठीक है कि लोगों श्रम को बचाते ही रहें जबकि हजारों आदमी बेरोजगार होते रहें और भूख से मरने के लिये खुली सड़कों पर छोड़ दिये जायें । मैं चंद आदमियों के लिये ही समय और श्रम नहीं बचाना

चाहता बल्कि सभी के लिये समय और श्रम बचाना चाहता हूं : मैं चंद लोगों के हाथों में ही सम्पत्ति को केन्द्रित नहीं करना चाहता लेकिन उसका वितरण सभी व्यक्तियों में कराना चाहता हूं । आज करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी छीन कर मशीनरी केवल कुछ ही लोगों की सहायता करती है । मशीनरी को प्रोत्साहन देना श्रम को बचाने वाली उदारता नहीं है अपितु इसमें निहित लालच है। ऐसी ही सभी बातों के विरुद्ध मैं अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहा हूं । "गांधी जी ने इसको कहा था। पंडित नेहरू जी के हाथ में जब हिन्दुस्तान की सत्ता आई तो उनके ऊपर पश्चिमी देशों के औद्योगिकीकरण का जो एक नकशा था, उनके दिमाग में जो पश्चिमी देशों का एक ढांचा था उसके आधार पर उन्होंने बात की और औद्योगिक रचना करने की सोची । नेहरू जी ने जो अपनी एक नीति अख्तियार की मैं उसको पढ़ कर सुनाना चाहूंगा । "जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में, जो 28 सितम्बर, 1959 को चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी, अपना भाषण देते हुए अपनी स्थिति को बिलकुल ही स्पष्ट कर दिया था । उन्होंने कहा : समेकित योजना के बारे में मुख्य बात उत्पादन है, रोजगार नहीं है । रोजगार का महत्व है लेकिन उत्पादन के संदर्भ में इसका बिलकुल भी महत्व नहीं है । रोजगार उत्पादन के बाद आता है, उत्पादन के पहले नहीं आता और उत्पादन अच्छी तकनीकों से बढ़ेगा, जो आज आधुनिक तरीके हैं"। "गांधी जी और जवाहर लाल नेहरु इन दोनों के विचार यहां टकराते हैं । गांधीवाद और नेहरूवाद का झगड़ा यहां से प्रारम्भ हुआ । वह मानते हैं कि उत्पादन के बाद रोजगार की सुविधाएं बढ़ेंगी । उत्पादन के पहले रोजगार की सुविधाएं नहीं बढ़ेंगी । मतलब यह कि घोड़े को गाड़ी के पीछे रखोगे, गाड़ी को घोड़े के पीछे नहीं । गाड़ी जब घोड़े के पीछे रहेगी तो पता है गाड़ी बहुत तेजी से चलेगी । उत्पादन से पहले रोजगार होता है । उत्पादन के साथ रोजगार जुड़ा होता है न कि उत्पादन के बाद रोजगार होता है । उत्पादन के बाद वितरण आयेगा । उत्पादन के बाद वितरण की व्यवस्था चालू करनी पड़ेगी । उत्पादन से पहले रोजगार होगा तो उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा । उत्पादन से पहले रोजगार होगा तो उसके लिये जरूरी होगा कि कैसे उत्पादन पद्धति लागू करनी होगी और कितने लोगों को काम मिलेगा । वहीं से रोजगार का काम चलता है । आप अपनी औद्योगिक नीति को बदलिये । मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि देश के अंदर, गांव के अन्दर आपकी औद्योगिक नीति से कितना नुकसान हुआ है । 1881 ईस्वी में जब देश में अंग्रेजो शासन था, उस समय खेती में 50.7 परसेंट आदमी लगे हुए थे । 1951 में 69.1 परसेंट लोग खेती में लगे हुए थे जब कि देश में आजाद भारत की सरकार बनी थी । 1881 में अंग्रेजों राज में उद्योग पर 36.3 परसेंट लोग लगे हुए थे जब कि 1951 में 13.6 परसेंट लोग उद्योग में आ गये थे । निरन्तर उद्योग पर से भार घटता चला गया । बेकारी बढ़ती चली गई और वह भार खेती पर बढ़ता चला गया । दुनिया का यह नियम है कि जिस देश में जितना ज्यादा खेती पर भार बढ़ेगा वह देश उतना ही गरीब होगा । मैं इसलिये कहता हूं कि अमेरिका जो सम्पन्न देश है वहां पर खेती पर आबादी का कुल 4 फीसदी आदमी लगा हुआ है । रूस में आबादी के केवल 30 फीसदी लोग खेती पर लगे हुए हैं ।

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

जापान में केवल 20 फीसदी आदमी खेती पर लगे हुए हैं । यह दुनिया के शक्तिशाली और ताकतवर देश हैं । हिन्दुस्तान में 100 में से 70 फीसदी लोग खेती में लगे हुए हैं । हिन्दुस्तान में रोजगार के साथ जाति व्यवस्था बंधी हुई है । लोहे के साथ, लकड़ी के साथ, चमड़े के साथ, मिट्टी के साथ और अन्य रोजगारों के साथ हिन्दुस्तान को जो जाति व्यवस्था बनी थी वह अब समाप्त होती जा रही है । जिस समय हिन्दुस्तान में यह जाति व्यवस्था बनी थी उस समय यह सोचा गया था कि उनके आर्थिक अधिकारों को सीमित करके खास-खास कामों के साथ उनको जोड़ दिया जाए । लेकिन आजाद भारत में और अंग्रेजों के जमाने में उनके हाथ से ये कारोबार छिनते चले गये । उनके हाथ से चमड़े का कारोबार छिन गया, गांवों से लोहे का कारोबार छिन गया, लकड़ी का कारोबार छिन गया । मेरे पास समय नहीं है, अन्यथा मैं आपको आंकड़े देकर बताता कि उनकी अब किस प्रकार की स्थिति हो गई है । हिन्दुस्तान के अन्दर सन 1931 में जो जनगणना हुई है उस जनगणना के मुताबिक बढ़ई, चमार, धोबी, दर्जी, खत्री, कुम्हार, लोहार, मोची, नाई, बंजारा, सुनार, तांती और तेली आदि लोग अपना अपना रोजगार करते हैं और उसी के आधार पर जातियां बनी हैं । आज सन 1971 की जनगणना में इनकी संख्या क्यों टूट गई है ? अफसोस है कि इस देश के अन्दर उनके हाथ के रोजगार छीन लिये गये । सारे रोजगार शहरों में लाये गये । अभी माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र विकल कह रहे थे कि सरकार ने बड़े बड़े उद्योग स्थापित किये, बड़ी बड़ी औद्योगिक नगरियां बनाई गई, सारे उद्योग शहरों में केन्द्रित कर दिये गये हैं । गांवों के लोगों को अपनी जमीनों से बेदखल कर दिया गया । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप प्राथमिकताएं तय कीजिये । प्राथमिकताओं को आप भूल गये । हमारे यहां गांवों में कहते हैं--उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान । सबसे उत्तम खेती है, उसके बाद दूसरे नम्बर पर व्यापार आता है, तीसरे नम्बर पर नौकरी आती है और चौथे पर भीख मांगना आता है । लेकिन आज आपने प्राथमिकताओं को बदल दिया । आज खेती उत्तम नहीं है, मध्यम व्यपार नहीं है, निकृष्ट नौकरी नही है और भीख निदान नहीं है । आज सबसे उत्तम नौकरी है, मध्यम व्यपार है, निकृष्ट भीख है और सबसे निदान खेती है । गांव का किसान धोती पहन कर या लंगी पहनकर कंधे में गमछा डालकर अगर किसी कार्यालय में जाता है तो उसको चपरासी भी इज्जत नहीं करता है । उद्योगों में लायसेंस हैं, परमिट हैं, कोटा हैं, लेन हैं, देन है और आमद-रफद भी है । खेती में न लायसेंस चाहिए, न परमिट चाहिए, न कोटा चाहिए और न ही आमद-रफद चाहिए । इसलिए उसको कोई नहीं पूछता है । इसलिए मैं कह रहा था कि आपने गलत प्राथमिकताएं निर्धारित कीं । यह उसी का परिणाम है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योग और खेती का क्या रिश्ता था । उसके बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और छटी पंचवर्षीय योजनाएं बनीं । लेकिन किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ । गांवों में कोई सुधार नहीं हुआ । इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपको

फिर से सोचना पड़ेगा और अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना होगा। आपने निजी क्षेत्र में कारोबार शुरू किए। बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को अपने कारोबार को बढ़ाने का मौका दिया। जब इनके बारे में आपसे प्रश्न किये गये तो आपने कहा कि हम इनको एम० आर० टी० पी० एक्ट से नियंत्रित करते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सन 1966 में इंडस्ट्रियल लायसेंसिंग इन्क्वायरी कमीशन ने बड़े बड़े घरानों के बारे में लिखा था कि उनके द्वारा कितने उद्योग चलाये जा रहे हैं। सन 1971 में कम्पनी विभाग ने क्या बताया है और फिर इसी विभाग ने सन 1977 में क्या बताया है, उस पर आप ध्यान दीजिये। सन 966 में टाटा के उद्योगों की संख्या 60 थी और सन 1971 भी यह 60 ही रही, लेकिन सन 1977 में यह 32 हो गई। इसी तरह से बिरला के उद्योगों की संख्या सन 1966 में 194 थी तो सन 1971 में 190 हो गई और सन 1977 में 70 हो गई। इसी प्रकार से मफतलाल के उद्योगों की संख्या सन 1966 में 20 थी तो सन 1971 में 20 रही और सन 1977 में 14 हो गई। बांगूर के उद्योगों की संख्या 1966 में 87 थी तो सन 1971 में 83 हो गई और सन 1977 में 44 हो गई। इन सब बीस औद्योगिक घरानों के आंकड़े देकर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। सन 1966 में जब आपने इंडस्ट्रियल लायसेंसिंग पालिसी इन्क्वायरी कमीशन बनाया था तो उसने यह रिपोर्ट दी थी। मैं पूछना चाहता हूं कि इन बड़े घरानों के उद्योगों की संख्या में कमी क्यों होती चली गई? इसका कारण यह था कि आपने एम० आर० टी० पी० एक्ट के अधीन इन कम्पनियों पर छोड़ दिया कि वे अपने को धारा 20 में रखें, या धारा 20 (ख) में रखें, या धारा 26 में रखें। उन्होंने इसका लाभ उठाया। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सच्चर समिति ने भी इन मामलों पर विचार किया था। और उन्होंने कहा था इस तरह कम्पनियों को छूट दी जा रही है और कम्पनियां गोलमाल कर रही हैं। बड़े घराने एम० आर० टी० पी० से अपने को बचा लेते हैं। लेकिन आज तक सरकार ने सच्चर समिति की सिफारिशों पर कोई विचार नहीं किया। बड़े उद्योगों को छोड़ते चले गये और वे स्वेच्छाचारी ढंग से अपनी सम्पत्ति को बढ़ाते चले गये। उनको कितनी छूट दी जा सकती थी दी गई और उनकी पूंजी बढ़ती चली गई और निजी क्षेत्र आर्थिक शक्ति का केन्द्र बन गया। आज बड़े-बड़े उद्योगों के हाथ में, हिन्दुस्तान के जो 20 बड़े औद्योगिक घराने हैं उनके हाथ में इन उद्योगों के मार्फत पूंजी का केन्द्रीयकरण हो गया है। आप यह देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि 1963 और 1971 के बीच में टाटा की सम्पत्ति में 96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बिरला की सम्पत्ति में 139 प्रतिशत की वृद्धि हुई, मफ़तलाल की सम्पत्ति में 411 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, थापर की सम्पत्ति में 101 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, आई० सी० आई० की सम्पत्ति में 270 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, श्रीराम की सम्पत्ति में 137 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार से बड़े-बड़े घरानों की जो सम्पत्ति बढ़ी है उसका मैं कच्चा चिट्ठा खोल सकता हूं, उनका इतिहास यहां रख सकता हूं। निजी क्षेत्र में सम्पत्ति का आपने केन्द्रीयकरण किया है और उनकी सम्पत्ति को बढ़ाने का काम किया है। इससे कितना देश को नुकसान हुआ है, कितना आप देश को नुकसान में डाल चले जा रहे हैं? आखिर में एक बात

[श्री हुकमदेव नारायण यादव]

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सार्वजनिक क्षेत्र में काम किये हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की है और बीमार उद्योगों, कमजोर उद्योगों करण उद्योगों को आपने अपने हाथ में लेने का काम किया है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 1981–82 में नकली समाजवाद का नारा देते हुए आपने कुछ काम किये हैं और पिछले वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है । 31 मार्च, 1951 को पांच उपक्रमों में जहां 29 करोड़ रुपये लगे हुए थे, 31 मार्च 1981 तक उनकी संख्या 185 हो गई और लागत 21 हजार करोड़ रुपये हो गई और 31 मार्च 1982 तक 203 उपक्रमों की लागत 24761 करोड़ रुपये हो गई और उसमें लगभग 15–16 सौ करोड़ रुपये का घाटा हुआ है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर जरा आप सोचें कि आपके द्वारा जो उद्योग चलाये गये हैं, औद्योगिक वित्त निगम के अध्यक्ष जी० एन० डावर के अनुसार, उन्होंने जो बयान दिया था उनके मुताबिक कितना घाटा हुआ है । लोक सभा में तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री चरणजीत चानना ने जो वक्तव्य दिया था उसके मुताबिक 18 सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था । यह कहां का इंसाफ़ है ? मैं पूछना चाहता हूं कि देश में 24 सौ करोड़ रुपये की पूंजी निजी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना पर आपने लगाई है और 18 सौ करोड़ रुपये घाटे में लगा चुके हो और जो यह 24 सौ करोड़ रुपये की पूंजी आपने लगाई है इस पर यह घाटा बढ़ते–बढ़ते अब 24 सौ करोड़ रुपये हो गया होगा । घाटा निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है । सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग निरन्तर घाटे में चले जा रहे हैं । आप उनमें कोई सुधार नहीं कर रहे हैं । मैं निवेदन करूंगा कि उनको सुधारने की कोशिश करिये और इसके लिये कोई रास्ता निकालिये और देखिये कि कहां–कहां खराबियां हैं, कहां–कहां गड़बड़ियां हैं । महोदय, सार्वजनिक उद्योगों को निरन्तर घाटे में ले जाने का काम चल रहा है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप यह कर दें कि हाथ का काम जहां हो वहां पर मशीन नहीं जायेगी और हाथ के काम में मशीन का दखल नहीं होगा । जो काम कुटीर उद्योग धंधों हो सकता है, वह बड़े उद्योग धंधों नहीं होगा । तेल बनाना, जूता बनाना, साबुन बनाना, कपड़ा बनाना इन सारे सामानों को हाथ के काम के क्षेत्र में रहने दीजिये और इन कामों को ये लोग करें ताकि चमार मरने न पाये, मोची मरने न पाये, जुलाहा मरने न पाये, कंगरेज मरने न पाये और जो ये पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जिनके छोटे उद्योग पीढ़ियों से चले आ रहे हैं उनको रोजगार मिल सके । लेकिन आज हिन्दुस्तान के उच्च वर्ग के हाथ में सब कुछ हैं । इसलिये उनका एक षड़यंत्र है और पूंजीवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के मेल से हिन्दुस्तान के पिछड़े और हरिजन, जिनके हाथ में हजारों करोड़ों वर्षों से वंशानुगत तरीके से ये उद्योग चले आ रहे हैं, उनसे वह छीन लिया जाये और उनसे इसको छीनकर वे बिरला, टाटा, गोयनका को सौंपने का काम कर रहे हैं । उसको उन्होंने गरीब कर दिया, मजबूर कर दिया भूखों मरने के लिये । यही गांधी के हिन्दुस्तान की देन है ।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए सरकार से निवेदन करूंगा, मैं माननीय तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि आप कांग्रेसी भी हैं और आपके सोशलिस्ट भी रहे हैं । आप न केवल कांग्रेसी हो, बल्कि आप सोशलिस्ट पयम्परा के भी रहे हो । इसलिये हम आशा करते हैं कि आपके हाथों से देश

की गरीबी दूर होगी। इसके लिये आप कठोर कदम उठाइये और नई उद्योग नीति की घोषणा कीजिये। आप नई औद्योगिक नीति की घोषणा करके देश को मजबूत करिये, काम यहां होने दीजिये और छोटे लोगों के हाथ में रोजगार देने का काम कीजिये। बड़े लोगों के हाथ से उदयोग को छीनिये और छोटे लोगों के हाथ में उद्योग दीजिये। आपसे मेरी प्रार्थना है बिहार जैसे प्रदेश के बारे में आपको सोचना पड़ेगा और वहां आपको ऐसा करना पड़ेगा। भाई रामानन्द जो भी बिहार के बारे में बोलेंगे, बिहार की बात कहेंगे और यदि मैं कहने लगूं तो कहेंग कि हमारी सरकार है आप उसकी आलोचना करत हैं। अब आप ही बताएंगे कि बिहार में कितने उद्योग विकसित हो रहे हैं। अशोक पेपर मिल, ठाकुर पेपर मिल की कहानी आप भी कहें और मैंने भी स्थिति आपके सामने रख दी है। मैं आपसे कहूंगा कि आप पार्टियों की बात छोड़िये आपको देखना है तो भारत को भयावह आर्थिक अवस्था पर गांधीवादी विचारों के आधार पर चौधरी चरण सिंह ने जो किताब लिखी है उस में उन्होंने आंकड़े इकट्ठे कर के दुनिया के अर्थ–शास्त्रियों के आंकड़ों को इकट्ठा करके बताया है कि देश की दिशा कैसे आप लोगों ने गड़बड़ की है। जरा इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग साफ़ होंगे और तब देखेंगे कि हिन्दुस्तान को आप किस दिशा में ले गये हैं। मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि मैंने ज्यादा समय ले लिया, मैंने बहस प्रारम्भ की है। मुझको यदि आधे घंटा, पैंतालीस मिनट समय मिल जाता तो मैं और व्यापक रूप से अपनी बात आपके सामने रखता और सब बातों का पर्दा–फाश करता और देश में गरीबों और झोंपड़ी में रहने वालों के कल्याण की बात करता। धन्यवाद।

श्री जे० के० जैन : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम इस सदन में उद्योग मंत्रालय के जो कार्यक्रम और कार्यकलाप हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और मुझे आपने दल की ओर से इस डिबेट में भाग लेने का जो अवसर मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री रामानन्द यादव : मेरा प्वाइंट आफ़ आर्डर है। यह जो आपके पास लिस्ट में हम सब लोगों का नाम दिया है, मांगा जाता है उस पर हम उन लोगों ने अपना नाम दिया है और उस लिस्ट मे कुछ लोगों का नाम अपीयर हुआ हैं। आप उस लिस्ट के आधार पर बुलाएंगे या दल के आधार पर हम लोगों को बोलने की इजाजत देंगे। हम चाहते हैं क्योंकि एक प्रक्रिया के अनुसार जिस तरह से। हम लोगों ने लिख कर रेजोल्यूशन दिया है कि हम इस पर बोलना चाहते हैं, हम लोगों ने परफोर्मा भर कर दिया है उसके आधार पर आज वह निकला है हम लोगों का नाम उसमें है कि अमुक-अमुक आदमी इस पर बोलना चाहते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आप जो लिस्ट निकाली है उसके अनुसार बुलाएंगे या दल के द्वारा दिये गये नामो के अनुसार ?

श्री शान्ति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सबको मौका दीजिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली) : आप तशरीफ रखिये। इसमें कोई प्लाइंट आफ आर्डर का सवाल नहीं है। दूसरा आप खुद जानते हैं यहां का तरीकाकार, फंकशनिंग जिस तरह से हाऊस का चलता है, पार्टीवाइज बुलाते हैं।

श्री रामानन्द यादव : ऐसा तो कालिंग अटेंशन का है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली) : जी नहीं, इसका यही तरीकाकार है। येस मिस्टर जैन।

श्री जे० के० जैन : उपसभाध्यक्ष महोदय 15 अगस्त, 1947 को जब भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झण्डा लहराया था उस समय उन्होंने यह कहा था कि आज हमारे युद्ध का प्रथम चरण पूरा हुआ है। आज हम राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं लेकिन इस प्रथम चरण के समाप्त होते ही हम दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं और वह दूसरा चरण क्या था कि हम को आज के बाद से आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संग्राम प्रारम्भ करना है। पंडित नेहरू के यह शब्द कोई उनके बनाए हुए शब्द नहीं थे बल्कि देश के उन करोड़ों गरीब स्त्री-पुरुषों, बच्चों, बूढ़ों के चेहरों के ऊपर जो उदासीनता, जो मलिनता उन्होंने देखी थी स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान गांव-गांव में जा कर गली गली में जा कर पहाड़ों में जा कर देश के कोने में जा कर उस के आधार पर पंडित नेहरू ने उस महान नेता ने यह शब्द लाल किले की प्राचीर से कहे। यही कारण था कि 1948 के अन्दर, आजादी मिलने के तुरंत एक वर्ष बाद औद्योगिक नीति का प्रस्ताव यहां पर लाया गया। उस प्रस्ताव के ऊपर बहुत चर्चाएं चलीं और 1956 के अन्दर एक औद्योगिक नीति की घोषणा कर दी गई।

इतना विशाल देश, इस विशाल देश की इतनी विशाल समस्याएं, इन विशाल समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ हिंदुस्तान और इतना विशाल समुदाय, यह मामूली बात नहीं थी। एक चुनौती देश के सामने थी।

अंग्रेजों को जिसने ललकारा था, वह अंग्रेज जो हमेशा यह दलील देते थे कि इस मुल्क के लोग यदि आजाद कर दिये गये, तो अपने पैरों पर कभी नहीं खड़े हो पायेंगे। अंग्रेजों ने शायद ठेका ले रखा था सारे विश्व की मानवता का। आज हमें यह कहते हुए फख्र है कि अंग्रेजों की बात गलत साबित हुई।

आपको याद होगा कि अंग्रेज जब इस मुल्क को छोड़ कर गये, तो उन्होंने इस मुल्क को ऊपर न उठने देने के लिए कुछ ऐसे-ऐसे कागजात छोड़ दिये जिनके ऊपर हम कई वर्षों तक कुछ काम नहीं कर पाये।

तेल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने कहा कि इस देश के अंदर तेल निकालने का कोई साधन नहीं है।

श्रीमन्, आप जानते हैं कि बिना आयल के देश का विकास होना एक स्वप्न के बराबर है, लेकिन यह पं० जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता थी---पं० नेहरू ने यह कहा कि हम ऐसा नहीं मानते कि इस देश में तेल नहीं है और इस विशाल देश की धरती अधिकारियों को भेज कर उसके ऊपर खोज करवाई और खोज के कितने परिणाम अच्छे निकले---आयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना की गई। देश के कोने-कोने में हमारे अधिकारियों और टैक्नीशनों ने जाकर तेल की खोज की और तेल निकला और किस मात्रा में निकल रहा है, यह देश में नहीं, विदेशों ताकतों से भी छिपा नहीं है। हम यहीं नहीं रुके, हमने समुद्र की तलहटी में जाकर तेल की खोज की है। समुद्र की तलहटी से तेल के फव्वारे निकल रहे हैं। गिर्ज बता रहा है कि विगत चार-पांच वर्षों के अंतर हमने किस तेजी से इस ओर प्रगति की है और मैं इस सदन के अंदर यह घोषणा करना चाहता हूं कि हमारे टैक्नोशन, हमारे नेता और हमारी सरकार और हमारी पार्टी इस ओर जरा सी भी बेतालूका नहीं बरतेगी और एक दिन आएगा कि हमारा देश तेल के मामले में सिर्फ आत्म-निर्भर ही न रह कर विश्व के अन्य देशों को तेल एक्सपोर्ट करेगा। हजारों, करोड़ों रुपये का विदेशी मुद्रा तेल को खरीदने में... **(व्यवधान)**

श्री सुशील चन्द महन्त : इन्फ्रा-स्ट्रक्चर .... **(व्यवधान)**

श्री जे० के० जैन : आप ठहरिये... (व्यवधान) इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात, आपको जानकारी नहीं है... (व्यवधान) जनाब आप गाड़ी बनवा लीजिए किसी फैक्टरी के अंदर तेल नहीं होगा, तो गाड़ी चलने वाली नहीं है । आप लकीर के फकीर बने हुए हैं क्योंकि—(समय की घंटी)—आपने जिन नेताओं की लीडरशिप एक्सैप्ट की हुई है, वह आपने दिमाग पर एक पीला चश्मा बन कर चढ़ा हुई है । आप उसको उतार कर के फेंको । औद्योगिक नीति का विकास किस प्रकार से कांग्रेस सरकार 1948 से लेकर अब तक बराबर करती चली जा रही है, किस प्रकार से देश के अंदर कारखानों का स्थापना हुई है—अभी मेरे विरोधी दल के भाई हुकमदेव नारायण यादव यहां बोल रहे थे, मुझे इस बात को कहते हुए दुख होता है कि जो उनके नेता उनको सिखाते रहे और पढ़ाते रहे, उनकी बू उनके भाषण में आ रही थी । नेहरू विरोधी नीति इन्हीं ने अपनाई । जनता पार्टी और लोकदल के शासन के दौरान इन मेरे विरोधी दल के भाईयों ने नेहरू की उस दूरदर्शिता को, नेहरू के उस नाम को मिटाने का दुस्साहस किया । मेरे विरोधी दल के भाइयो, नेहरू के नाम को मिटाने के लिए आप को राउरकेला को मिटाना पड़ेगा, आप को भिलाई को मिटाना पड़ेगा, आप को डैम तोड़ने पड़ेंगे, आप को नेहरू के द्वारा स्थापित कल-कारखानों को तोड़ना पड़ेगा । आप नेहरू के नाम को मिटा नहीं सकते और आप का यह दुस्साहस कभी पूरा नहीं हो सकता। यह नेहरू की दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज हिन्दुस्तान विश्व की महान शक्तियों में एक बनता चला जा रहा है । हरित क्रांति के बाद यह देश औद्योगिक क्रान्ति की ओर तेजी से बढ़ रहा है । यह हमारी पार्टी की, हमारे नेताओं की दूरदर्शिता का सफल परिणाम है ।

श्री सुरेश चन्द्र महन्त : नौवां नम्बर है।

श्री जे० के० जैन : मैं फिर कह रहा हूं कि इन के ऊपर कुछ और चश्मे चढ़े हुए हैं। एक ओर यह कहते हैं कि हिन्दुस्तान की आबादी 70 करोड़ है। अरे मेरे प्यारे भाइयो, 70 करोड़ इनसानों की बहबूदी का ध्यान रखते हुए हिन्दुस्तान औद्योगिक क्रान्ति की ओर बढ़ रहा है । आप उन मुल्कों से तुलना मत कीजिए जिन की आबादी दो करोड़, तीन करोड़, आठ करोड़ या दस करोड़ है । यहां की समस्याएं विकराल हैं क्योंकि यहां की आबादी इन सब मुल्कों की आबादी को अगर जोड़ दिया जाय तो उस से भी दुगुनी-तिगुनी बैठेगी । और मैं यह बड़े दावे से कहता हूं कि नवें-दसवें की बात नहीं, आबादी के हिसाब से हिन्दुस्तान के अन्दर जो औद्योगिक क्रान्ति हो रही है वह किसी मुल्क से कम नहीं, उस से बहुत ज्यादा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भाइयों को शार्ट-साइटेडनेस की पोलिसी को छोड़ना पड़ेगा । एक मुल्क जो तेजी के साथ विकास की ओर बढ़ रहा था 1977 के अन्दर एक ऐसा देश के ऊपर आघात हुआ जिस की वजह से औद्योगिक धन्धे ही नहीं, सारा देश चरमरा गया, ऐसे लोग शासन को संभाल कर बैठ गये जिन्होंने उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा नहीं की थी । वह नहीं जानते थे कि तमिलनाडु किधर है, उड़ीसा किधर है, आसाम किधर है, मिजोरम-नागालैंड किधर है, वह कुएं के मेढ़क के समान कुएं के अन्दर की बने रहे । लेकिन दुर्भाग्य था इस देश का कि जनता इन लोगों की बात में आकर बहक गयी और उस ने इन को देश के शासन पर बिठा दिया । लेकिन ढाई वर्ष के अन्दर ही उन को करारी हार का मुंह देखना पड़ा और 1980 के अन्दर जब देश की प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने शासन की बागडोर एक बार फिर संभाली तो उन्होंने मंच से खड़े होकर यह कहा था वह इन

[श्री जे० के० जैन]

के जिस भी काम को देखती हैं उसमें खोखलापन नजर आ रहा है । औद्योगिक स्थिति को इन्हों ने बिगाड़ कर रख दिया । तेल का जो आयात करते थे उस की बुकिंग नहीं की । आप लोग भूल गये किस तरह हजारों ट्रक, टैक्सी, कारों और स्कूटरों की लाइनें लगती थीं पेट्रोल पम्प के ऊपर । उपाध्यक्ष महोदय, यह लोग जानते हैं कि इनकी नीतियों ने देश को बरबादी के कगार पर पहुंचा दिया था, इसी लिए इन को आयल की बात पसन्द नहीं आयेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी विडम्बना है, फोगर्स को भी यह लोग झुठला सकते हैं क्योंकि जिस चीज की आधारशिला ही असत्य है उसमें से असत्य ही निकलता है । सच की ओर इनकी नजर ही नहीं पड़ सकती । मुझे फोगर्स में जाने की आवश्यकता नहीं । किताबें छपी पड़ी हैं। यदि इनको पढ़ना नहीं आता तो किसी को बुला लें, वह इन को पढ़कर सुना दे । कुछ बातें मैं इनको जरूर बताना चाहूंगा कि किस तरह से इंडस्ट्रियल इकोनोमी में इन्क्रीज हुई है—1980–81 में 4 प्रतिशत, 81–82 में 8.6 परसेंट । 1982–83 में जबरदस्त ग्रोथ हुई है और स्माल सेक्टर के अंदर 1980–81 और 1981–82 तक 10 परसेंट हुई है और 1982–83 में 7 प्रतिशत हुई है और प्रोडक्शन 1981–82 में 32,000 करोड़ का हुआ है । यह मैं स्माल सैक्टर की बात कर रहा हूं । मेरे अच्छे मित्र हुक्मदेव नारायण जी गरीबों की बात कर रहे थे कि धोबी बेरोजगार हो गया, नाई बेरोजगार हो गया, चर्मकारों को काम नहीं मिल रहा है, बढ़ई कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं । क्या क्या बातें उन्होंने कही । मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूं कि 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ था हमारे इन वर्गों के कितने भाई आईपी एस की नौकरियों में थे, कितने भाई देश के प्रशासन में आई सी एस और आई ए एस में थे? कितने भाई आर्मी की कमांड को सम्हाले हुए थे? कितने भाई छोटे उद्योग धंधों में लगे हुए थे, कितने भाई व्यापार में लगे हुए थे? इन्हीं के मुंह की कही हुई बात को मैं कह रहा हूं कि यह कहते हैं कि काम नहीं मिल रहा है और मैं दूसरी तरफ कहता हूं कि 1982–83 में इन लघु उद्योग धंधों में लगे हुए 80 लाख व्यक्ति जो हैं उन को क्या हुक्मदेव नारायण जी विदेशों से लाये हैं। यह इसी देश के लाल हैं । यह इसी देश के सपूत हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा छोटे-छोटे उद्योग स्थापित कर के अपने को बारोजगार बनाया है । यह चरणसिंह की नीति हो सकती है कि यदि कोई बढ़ई सिर पर बोरी में अपने औजार रख कर काम कर रहा है तो वह अपना कारखाना न लगाये।

The Vice-Chairman (Shri R. Ramakrishnan) in the Chair.

मुझे तो यह कहते हुए बड़ा गर्व है कि 1947 का वह बूढ़ा बढ़ई जो अपने हाथ से काम करता था उस ने अपने बच्चे को आई टी आई में भेजा, उसको ट्रेनिंग दिलाई और उस के लिये एक छोटा उद्योग स्थापित कर दिया । किस तरह से देश में चंमुखी विकास हो रहा है लेकिन हमारे भाई हर चीज को एक गंदी राजनीति की दृष्टि से ही देखते हैं।

एक्सपोर्ट के फिगर मैं आप को बता दूं । यह छोटे उद्योग धंधों के फिगर हैं और किताबें भरी पड़ी है कि इन उद्योगों में किन-किन वर्गों के लोग काम कर रहे हैं । यह उन्हीं वर्गों के लोग हैं जिन के लिये हुक्मदेव नारायण जी ने अभी घड़ियाली आंसू बहाये हैं । इन्हीं छोटे

उद्योग धंधों में लगे हुए हमारे इन भाइयों ने 1982-83 में 2095 करोड़ रुपये का सामान निर्यात किया । कितना निर्यात 1947 में हुआ करता था, जरा बताइये। आप ही लोग कहीं पर चर्चा करते हुए सुनाई देते हैं कि हिन्दुस्तान वह मुल्क था जिस में सुई भी नहीं बनती थी । यदि सुई इस देश में आती थी तो उस के बदले में सोना बरतानिया चला जाता था । और अब कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि यह वही देश है कि जिस के अंदर सुई नहीं बनती थी, लेकिन अब इस देश के अंदर हैलीकोप्टर ही नहीं, हवाई जहाज ही नहीं, दुश्मनों के दांत तोड़ने वाले टैंक भी इस देश में ही बन रहे हैं । इस देश के अंदर पनडुब्बियों का भी निर्माण हो रहा है । जाइये, विशाखापट्टनम में जा कर देखिये । उन शिप यार्ड्स में जाकर देखिये कि किस तरह से सामान ढोने वाले और जंगी जहाज वहां बन रहे हैं । रिफाइनरीज को देखिये कि किस प्रकार से तेल को लाइनों से भेजा जा रहा है और देश के कोने-कोने में तेल पहुंचाया जा रहा है । चितरंजन लोकोमोटिव को जाकर देखिये । हुकमदेव जी को तो यहां बैठने की हिम्मत नहीं है, वह चले गये । यह चितरंजन लोकोमोटिव किस की दूरदर्शिता का परिणाम है । यह नेहरू जी की नीतियों का परिणाम है । आज हम इन चीजों का सुख ले रहे हैं । आज इसी सदन में मांग की जाती है कि रेल की पटरियां बिछाइये । रेल के डिब्बों की कमी है, हम को वैगन्स नहीं मिलते ।

इंजिन का सुधार होना चाहिए, डीजल इंजिन आने चाहिए क्यों मांग करते हैं ? मेरे प्यारे भाइयो, इस देश के अन्दर एक तरफ़ मांग करते हो, एक तरफ़ मशीन युग की भर्त्सना करते हो और दूसरी ओर हिन्दुस्तान जैसे गरीब मुल्क को औद्योगिक मुल्क बनाने वाले राष्ट्रनेता पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की भर्त्सना करते हुये आपको लाज नहीं आती ।

अध्यक्ष महोदय, हैवी इंडस्ट्रीज के अन्दर कितना उत्पादन हुआ । 1980-81 में 1297 करोड़ रुपये की राशि का उत्पादन हुआ । 1983-84 में यह बढ़कर 2257 करोड़ हो गया और जो उत्पादन 1981-82 में 1297 करोड़ का था, वह चार वर्षों के अन्दर बढ़कर 2810 करोड़ हो गया । अध्यक्ष महोदय, हमारे भाई जो भी कह दें, हमारी नीतियों की आलोचना करें, लेकिन ये फीगर्स को नहीं झुठला सकते । देश के अन्दर जो चौमुखी विकास हो रहा है, देश के अन्दर जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, फ्लाई ओवर्स बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, पटरियों के जाल बिछाये जा रहे हैं, देश के कोने कोने में बिछाए जा रहे हैं, मोटरों की लाइनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, ये सब इन कारखानों से निकलते हुए, उगलते हुए लोहे के कारण हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक बातें और राजनीति की चर्चा हर चीज में जाना, देश के विकास के अन्दर रोड़े अटकाना है क्योंकि 1977 की बातें जब याद आती हैं तो इनका पर्दाफाश हो जाता है । क्या हुआ इनके मंत्रियों को । जार्ज फरनान्डीस इस देश के उद्योग मंत्री बने । बताइये क्या नीतियां उन्होंने अपनाई देश के औद्योगीकरण के लिए ? हां, एक नीति जरूर अपनाई थी कि कांग्रेस जनों में किसी-किसी के उद्योग लगे हुए हैं, उनके उद्योग धंधों के लाइसेंस नष्ट कर दो। हजारों मजदूरों को बेकार कर दो । बदले की भावना से इन लोगों ने औद्योगिक नीति नहीं बल्कि बदले की नीति मंत्रालय की कुर्सियों पर बैठकर बनाई। ...(व्यवधान)...

श्री अश्विनी कुमार (बिहार) : कोका कोला किसने खत्म किया था ...(व्यवधान)

श्री जे० के० जैन : मैं जानता हूं, शायद आप सिफारिश जरूर करने गए थे। श्रीमन्, इनको कोका कोला याद आ रहा है, दूसरी चीजें ये भूल गए। ... (**व्यवधान**)

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र) : आपको तकलीफ क्यों हो रही है ?

श्री सुशील चन्द्र महन्त : यह तो इंडस्ट्रियालाइजेशन हो रही है देश की। ...

श्री जे० के० जैन : देश की जो नीतियां थीं, जिनको 20 सालों से अनुभवों के बाद स्थापित किया गया था, वहां इनके प्रधान मंत्री देश की नीतियों में भी खिलवाड़ करते रहे। मोशे दायान को चोरी छिपे दिल्ली बुलाया गया ... (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : ये इंडस्ट्रियल पालिसी पर बोल रहे हैं ... (**व्यवधान**)

श्री जे० के० जैन : तकलीफ मत मानो, जरा सुनने की ताकत रखो। अध्यक्ष महोदय, मोशे दायान से चोरी छिपे प्रेमालाप तुम्हारी जनता पार्टी और लोकदल के लोग करते रहे। अरब के मुल्क क्यों इनका साथ देते हैं, आप क्यों इनका साथ देते हैं ? ... (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Only If such matters are introduced, the debate will become lively..

श्री जे० के० जैन : अध्यक्ष महोदय, अरब देशों का नाराज होना स्वाभाविक था। क्या हुआ ? तेल को प्रोक्योर करने में हमको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? किसी भी देश की चाहे वह व्यापार नीति हो, या औद्योगिक नीति हो या शिक्षा नीति हो, हर चीज की नीति बनाते समय, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम को विश्व को देखना पड़ता है, उसकी नीति को देखना पड़ता है, विश्व की विदेश नीति को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन ये विदेशनीति विहीन लोग, दिशाविहीन लोग क्या कोई नीति बना सकते थे, नहीं। इन्होंने तो बनाई हुई नीति को भी तोड़-मरोड़ करके फेंक दिया। सोना इन्होंने बिकवाया। बात करते हैं उद्योग पर डिबेट चल रही है। सोना नहीं होगा तो आपके देश के साथ कोई इंडस्ट्रियल कोलाबरेशन करने का तैयार नहीं होगा। इस सोने से देश की शक्ति को आंका और नापा जा सकता है। एक और आप सोना बेचते हैं, सोने की नीलामी करते हैं और दूसरी ओर बात करते हैं उद्योग की (**व्यवधान**)

SHRI SURESH KALMADI: I hope all of us will get the same amount *of,* time as Mr. J. K. Jain. He has spoken totally irrelevant things for the last half an hour.

SHRI J. K. JAIN; I will speak for one hour. See the strength of my party one hour. See the strength of my party party. See my block here; there are 153 Members of the ruling party. So, please don't interrupt.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): You go on with your speech. You don't allow them to sidetrack you.

{interruptions)

SHRI J. K. JAIN: Whatcan I dowhen they talk like this? Myparty hasso many Members and wehave the time....

श्री हुकमदेव नारायण यादव : एक शेर कई बिल्लियों से ज्यादा मजबूत होता है।

श्री जे० के० जैन : गीदड़ शेर का लिबास पहन ले तो उससे वह शेर नहीं बन जायेगा। आप शेर की खाल पहन कर बैठे हुए हैं। (**व्यवधान**) क्योंकि इनका नाम देव है इसलिये मैं इनको हमेशा देव कहता हूं।

श्री सुशील चन्द महन्त : आप डरते हैं, आप देखेंगे कि चुनाव में वही हालत फिर से होगी जो पहले हो चुकी है ।

श्री जे० के० जैन: कारवां जब चलता है तो वह चलता ही रहता है, वह कारवां रुकता नहीं है । (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN); Hon. Members, I request you in the interests of a proper debate you allow him to speak as he likes. You will get your chance when you say what you want. *{Interruptions)*

SHRi J. K. JAIN: Please don't interrupt me, Mr. Suresh Kalmadi. Yon are not flying in the air; now you are sitting in Rajya Sabfca, Please earn some manners .... *Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Please let him; continue.

SHRI SUSHIL CHAND MOHUNTA: He can speak till 6 o 'clok; we have no objection. We will continue tomorrow.

श्री जे० के० जैन: : मैं इस बात का पक्षपाती हूं । जिस प्रकार से हमारे देश की सरकार ने लघु उद्योग को प्रोत्साहन दिया है । आज हजारों, लाखों नौजवान हमारे देश की बनाई हुई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों, कालेजों, विश्व-विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करके निकल रहे हैं । आज इस बात की जरूरत है कि कुछ ऐसे उद्योग की नीति अपनाई जाए जिस नीति से हजारों, लाखों यंग इन्टरप्रेन्योर्स, एजुकेटिड इन्टरप्रेन्योर्स को काम करने का मौका मिले और देश के लिये उत्पादन बढ़ा सकें । देश में समृद्धि ला सकें । हमारे समक्ष जापान की मिसाल है । जापान किस प्रकार से 30 वर्ष के अंदर विश्व में एक औद्योगिक शक्ति बन गया । वह जापान जिसके पास रा-मेटिरियल नहीं था, वह जापान जिसके पास आयल नहीं था, माननीय सदस्य फिर कहेंगे कि आयल की बात क्यों करते हैं, उद्योग की बात क्यों नहीं करते (व्यवधान) आप विदेशियों के पक्षपाती हैं इसलिये आप आयल की बात पसंद नहीं करेंगे । यह विदेशी मामला हैं मैं आयल का पक्षपात जरूर करूंगा । (व्यवधान) किस प्रकार से जापान ने औद्योगिक प्रगति की, वही जापान है, हम उसे भूले नहीं हैं, 30 साल पहले जिसका सामान फुटपाथ पर आवाज दे-देकर बिकता था कि हर माल मिलेगा चार आने । लेकिन उस माल को कोई छूता नहीं था । रिजल्ट क्या हुआ है कि जापान का नवजवान जो उस समय शिक्षा के क्षेत्र में था जो अध्ययन कर रहा था, अध्ययन करने के बाद जब उसने तरुणाई में प्रवेश किया तो एक क्रांति उस देश के अन्दर आई और वहां की सरकार ने उन नवयुवकों की शक्ति को किस प्रकार से इस्तेमाल किया, यह सभी जानते हैं । हमारे कुशल मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल के अन्दर किसी प्रकार से लघु उद्योगों को बराबर प्रोत्साहन मिल रहा है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है । एक बार चाहे वे किसी बड़े उद्योग धंधे को प्रोत्साहन न दें, लेकिन जहां पर लघु उद्योगों की बात होती है, यंग इन्टरप्रेन्यौर्स की बात होती है तो किस हमदर्दी के साथ उसका साथ देते है, यह सब लोग जानते हैं । मैं उनसे निबेदन करूंगा कि जापान किस प्रकार से नये उद्यमियों को प्रोत्साहन दे रहा है, उस पालिसी का थोड़ा-सा वे निरीक्षण करायें । अभी जापान के प्रधान मंत्री इसी संसद् के सेन्ट्रल हाल में आए थे और किस प्रकार से उन्होंने भावभीनी शब्दों में आश्वासन दिया था

[श्री जे० के० जैन]

वह सभी ने सुना है । उन्होंने कहा कि हम हिन्दुस्तान के साथ हाथ से हाथ मिलाकर सहयोग और काम करना चाहते हैं । मैं उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हाल के जापान के प्रधान मंत्री जी को यात्रा का लाभ उठाकर तुरन्त ही एक दल जापान भेजें और वहां से इस चीज की रिपोर्ट मंगाई जाय कि किस प्रकार से वहां औद्योगीकिकरण हो रहा है ताकि हम भी अपने नौजवानों को उद्योगों की ओर प्रेरित कर सकें ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से अपनी सरकार को देना चाहता हूं । आर्थिक क्रांति लाने के लिए औद्योगीकिकरण की गति को तेज किया जाय । युवकों का उद्योगों की तरफ रुझान पैदा किया जाय । मौजूदा लघु ईकाइयों को अधिक संरक्षण देने के लिए विस्तृत विधेयक लाया जाय । गांवों के कारीगर लोहार, मोची, नाई वगैरह की ग्रुपिंग करके उनको बढ़ावा दिया जाय । आप जानते हैं कि ये लोग गांवों में गरीबी में रहते हैं । यदि भारत सरकार कुछ इस प्रकार की योजना बनाये जिसमें गांव के अन्दर इन कारीगरों का ग्रुपिंग करके, इन लोगों को इकट्ठा करके उनके लिए कारखाने स्थापित किये जायें । वहां पर ऐसे उद्योग धंधे स्थापित किये जाएँ ताकि इन लोगों के स्तर में अभी जो सुधार हो रहा है वह और भी आगे बढ़ सके । यह काम जिला औद्योगिक केन्द्रों के माध्यम से कराया जाय । सब उद्योगों का आधुनिकीकरण हो । आप अभी भूले नहीं होंगे, बम्बई के अन्दर महाराष्ट्र में कपड़ा मिलों की जो हड़ताल हुई थी उससे किस प्रकार से हिन्दुस्तान के कपड़ा उद्योग को धक्का पहुंचा था और तकलीफ हुई थी । उन कारखानों के अन्दर पुरानी मशीनें लगी हुई हैं । मैं समझता हूं कि आज विश्व में व्यापार करना कोई आसान चीज नहीं है । विज्ञान और विज्ञापन के युग में हर क्षेत्र में मुकाबले में खड़े होकर आपको अपना सामान बेचना होता है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां एक ओर उन 14 मिलों के अन्दर काम करने वाले हजारों श्रमिकों की रोजी रोटी का ध्यान रखकर और यह परवाह न करते हुए कि भारत सरकार के ऊपर इससे करोड़ों सैकड़ों का बोझ पड़ेगा, आपने उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके लिए जहां-मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं वहां इस बात के लिए भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय-कृत मिलें हैं और जो प्राइवेट सेक्टर की मिलें हैं उनके आधुनिकीकरण के लिए आप कुछ ऐसे साधन जुटाइये जिससे उन मिलों का आधुनिकीकरण हो, हमारे देश के लोगों को अच्छा और सस्ता कपड़ा मिल सके और साथ ही विश्व की मंडियों में जाकर हम अपने कपड़े का व्यापार अच्छे रूप में कर सकें। सार्वजनिक उद्योगों की बात श्री हुकमदेव नारायण यादव ने कही और कहा कि उनमें हजारों रुपयों का घाटा हो रहा है । अरे हुकमदेव नारायण यादव जी, यदि भारत सरकार अपनी सन् 1956 की औद्योगिक नीति के तहत सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना न करती तो शायद आज हम पाकिस्तान

5 p. m. की तरह ही दूसरे देशों के गुलाम बनकर उनके आगे हाथ फैलाकर एक एक चीज की भीख मांगते रहते होते। सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना सिर्फ लाभ को ध्यान में रखकर नहीं की जाती, सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना इसलिये की जाती है ताकि देश की जनता को किसी चीज की तकलीफ न होने पाये चाहे देश के खजाने

से सरकार को इसके लिये कितना ही खर्चा क्यों न करना पड़े । देश के नागरिक और देश पहले है, धन देश के लोगों की बहबूदी के लिये है । इसलिए सार्वजनिक उद्योग इस तरह से जद्दोजहद करते हैं । आप कहते हैं कि सार्वजनिक उद्योगों के अंदर इतना इतना घाटा हुआ करता है । लेकिन आज हमारे देश में बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा उत्पादन किया है और बहुत अच्छा लाभ भी दिया है । मैं अपने विरोधी दल के भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से हर वक्त, हर चीज पर निरुत्साहित करने की कोशिश न करें । आप दो शब्द अच्छे भी कहा करें जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिले । श्री हुक्मदेव नारायण के घर में बालक भी होगा । जब उनका बच्चा अच्छा काम करता है तो वह उनकी पीठ थपथपाते हैं कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया । लेकिन यदि हर काम में, अच्छे काम में भी बिगड़ते रहेंगे तो एक दिन वह आयेगा कि वह क्लास में पास होने के बजाय फेल होता रहेगा ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : पाकेट मार हो तो ?

श्री जे० के० जैन : पाकेटमार ? हर बच्चे को आप पाकेटमार समझते हैं ? क्या आप पाकेटमारों की जमात में बैठे हैं ? अगर ऐसा है तो आप उनकी जमात से निकलिये । 1977 में आपने पाकेट मारी थी, इसीलिये ढाई साल के अन्दर सब तहस नहस हो गया । अगर सच्ची कमाई होती तो आप पूरे पाच वर्ष तक रहते ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इन्हीं सुझावों के अन्तर्गत मैं अपने माननीय कुशल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 20-सूत्री कार्यक्रम जो आज हिन्दुस्तान के लाखों करोड़ों गरीब व्यक्तियों की आशा का केन्द्र बन गया है, हजारों लाखों व्यक्तियों को किस प्रकार से निरन्तर रोजगार मिलता रहे, किस प्रकार से सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के अन्दर छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित किये जायें, इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने मंत्रालय में एक विशेष सेल बनायें जिससे बीस-सूत्री कार्यक्रम पर जो अमल हो रहा है उसमें तेजी लाई जा सके । उपसभाध्यक्ष महोदय, उद्योग धंधों के ऊपर जब फाइनेंस का अंकुश आ जाता है तो उन उद्योग धंधों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है । मैं जानता हूं, अभी हमारे विरोधी दल के भाई चहक उठेंगे क्योंकि उनको हकीकत मालूम नहीं है । आज हमारे मारुति उद्योग की गाड़ियों के लिये यही लोग घूमते हुए आ रहे हैं कि हमें मारुति गाड़ी दे दीजिये । इनको नहीं मालूम कि यह स्वर्गीय संजय गांधी, मैं रिकार्ड की बात कह रहा हूं कि किस प्रकार बैंकों का अंकुश बराबर मारुति के ऊपर लगा रहा । मैं निवेदन करता हूं कि फिर कभी ऐसा दास्तान, मारुति उद्योग की घटनाओं की पुनरावृत्ति और उस तरह की परेशानी किसी नौजवान को न उठानी पड़े । आपको यह चाहिए कि आप वित्त मंत्रालय के साथ कोआर्डिनेशन करके बैंकों का जो अंकुश, छोटे, लघु और मध्यम दर्ज के उद्योगों के ऊपर है उसको कम करायें । हमें इसमें दूरदर्शिता रखनी चाहिए । यदि हम उनको खुलकर पैसा देंगे तो वह हमें खुलकर उत्पादन देंगे और अधिक उत्पादन देश में होगा और देश का उत्पादन बढ़ेगा । उपसभाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूं और जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी से इस उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद अपने कार्यों से देश के अंदर एक आशा की किरण जगाई है उसी प्रकार से आप उस किरण को मशाल बनाकर देश को जगाते रहेंगे और देश का एक-एक नौजवान जब तक रोजगार प्राप्त न कर लें, जब तक कोई

[श्री जे० के० जैन]

छोटा मोटा उद्योग धंधा न अपना ले तब तक इसके लिये अथक परिश्रम करते रहेंगे, इन शब्दों के साथ मैं आपको फिर बधाई देता हूं ।

SHRI R. MOHANARANGAM (Tamil Nadu); Mr. Vice-Chairman, Sir, after a very long time, that too after listening to the speeches of Mr. Yadav and my friend Mr. J. K. Jain, I an given the opportunity to speak in the discussion on the working of the Minis try of Industry. I am not going to give answers to questions raised by Mr. Iain, because it is not my duty. Rather I am going to endorse the views of Mr. Yadav as well as Mr Jain. But as a citizen of this country I know fully well, and if any person says that our country is not industrially developed, even a blind man will not accept that theory. If you go through the length and breadth of our country you will see that it is industrially developed to the satisfaction of almost all. But my fear is whether it has been properly distributed. That is the question I am going to raise.

It is a well known fact that our countiy is agricultural country. Eighty per cent of the total population of this country are completely dependent upon agriculture. That is why, Sir, by the time when the First Five Year Plan was framed, importance was given only for agriculture, considering the development of the agricultural community of this country. Only after having completed —I do not know whether it has been successfully completed or not— only after having completed the First . Five year Plan, thcy have started giving importance to it in the Second, Third, Fourth and Fifth Plan, with a view to industrialise our country. That is why they have given much importance for the industrial development of this count.

As I said already, our country is very, very, very important country *tat* agrio* hire. Eighty per cent of the population of this country is completely dependent upon agriculture. That is why, Sir, by the time when the Firss Five Year Plan was framed, importance was given only for agriculture. Bat after 37 years after independence, if anybody asks the question whether wo have developed to the satisfaction of all, it can be said that of course, we have somewhat satisfied the needs of the people. Whether we have fully satisfied these needs, this is what we have to discuss.

Mr. Jain has said that we have solved almost all problems, we have solved the industrial needs of the country. But finaly, Sir, he has not accepted the theory what he said. He has stated our Minister that he should take proper steps to develop the industrial system of this country, and therefore I request him to see that we have to develop our country.

What have we to do for this? We have-to improve the small-scale industry. Even Mr. Yadav as well as Mr. Jain of the ruling party have pointed out that the small scale industry should be started in each nook and corner of this country, especially in the rural area to create em loyment opportunities.

What is the object of the industrial policy? Even a first year student of Economics will say clearly that there are three objects of the industrialisation of the country. One is to create employment opportunities, another to produce mors and third is to tackle the entire poverty of this country. If we have to tackle the poverty of this country, we have to create employment opportunities to the satisfaction of all. Whether we have pro-ducd more for the needs of the country we have to study and understand whether we have completed all these things. But one thing we have to keep in our minds that until and unless we give importance to small scale industry, until and unless we ask our people to create employ-ment through the small scale Industry almost in all States of the country. we cannot achieve our target, target of giving employment to almost all adults of

this country. I want to ask one question of the Minister of Industry. I have got very high regard for our Minister. Whenever I go to him, never he will say no. He used *to* say 'yes', and he will ask his officers to take up the entire responsibility of satisfying me by giving proper answers, I get very good answers. But whether my problem is solved or not, I have to give proper answer for it. I ask: What is our industrial policy? What about the recommendations which they send, the applications for registration with the D. G. T. D,, and also for issue of Letter of Intent by the Government of India? Is it not our duty to give permission for *the* persons who come from the States for Letters of Intent as well as ' their duty to start industry in their own States. Is *it* mot the duty of the Government to encourage these persons and give incentives to them to start industries there? Tamil Nadu, I may tell you Mr Vice-Chairman, sent 110 applications for the Letters of intent, whereas the Government of India sanctioned only 57—57 out of 108 sanctioned for the year 1980. In 1981, *44* were sanctioned Out of 92. In the year 1982_f only 67 were sanctioned out of 184. Out of a total of 384, 123 applications are still pending with the Government of India. I do not know at what stage exactly the matter stands and what they are going to do for the 123 applications which are still pending with the Government of India. These are the main things I want to ask. But at the same time, I want *to* -fell him that if anybody comes forward saying that there is industrial progress in Tamil Nadu, it is not because of the recommendation by the Government of India, not because of the help rendered by the Government of India and not because of the services rendered by the Government of Tndia. but because of the importance given to industries by the Government of Tamil Nadu. We have developed. Somewhat in our State. For example from the year 1977 to 1983. for the past six years 449 medium and major scale industries have been set up in Tamil Nadu with an investment of 850 crores of rupees, whereby creating employment opnortiuiites of I, If,000 people, we have spent 850 crores of rupees without help of the Government of India, that too in the past six years by starting major and mdium seal industries, Thus, we have provided employment opportunities for more than 1 lakh of people. That is how we are going about the development of industries in my State.

What about the central investment? That is a very big question. I think the Government of India is situated not only in Delhi. It is also situated at Kanya Kumari and Jammu and Kashmir, i. e. throughout the length and breadth of this country consisting of 72 crores of people. The Government of India have to take up the entire responsibility for the industrialisation of this country or for the development of industry in this country. They have the responsibility for the entire 72 crores of people who come from Kanya Kumari or from Jammu and Kashmir. The entire country belongs to the Government of India. That is why I am asking* this. What have you done for the past 15 years or. I can say, for the past 17 years, since 1967, especially after the non-Congress party had taken up the responsibility of giving a good rule to the five crore citizens of Tamil Nadu? Of course, they have started some very big indus tries in Tamil Nadu. But till the year 1967, only 11 industries were started in Tamil Nadu, i.e. till the Congress was ruling that particular State from 1947 to 1967. Now, in 20 years they have started 11 industries in the Tamil Nadu State. But after 1967, Sir, I have been searching , the industrial map of this country and every nook and corner of my area and I find that only two industries, that loo of-moderate size have been started, that too in the year 1983. For the past 17 years, the Govenment of India never came forward, whether it was the rule of the Janata Party or of the Congress Party. With both the parties we had alliance. But none of these parties came forward-to start industries in our State. I Would-like the Minister to give me a specific._ answer. What is the reason for that

IShri R. Mohanarangam] Had any Minister belonging to a different party approached you or had anybody else had approached you not to start industries in our State?

As 1 said nearly 123 applications are pending with the Government of India or the past so many years. Why have you not taken steps to start industries anywhere in Tamil Nadu? At the same time, we are not quite satisfied with the central investment. It is reduced from, 8 per cent to 4 per cent in the year 1967. 1 do not know to what percentage they are going to reduce it further. What about the industrial procedure? A person comes from our area and approaches an officer. Do you mean to say that. the officer gives a proper reply to the questions raised by the persons who come with the intention of starting industries? I like you very much and I have got highj regard for you Bui what about the officers? They have got readymade answers for everything. As the Chairman of the Municipality. I was managing, 400 to 500 persons. Whenever I wanted to do anything for a person. T would give a very good answer. If I did not want to do the work, T would ask my officers to say that the rules don't permit it. Likewise, your officers, whenever they are approached for any licence are saying that this is not permitted by the rules and regulations. The rules were framed even before 1947, and your orticcr will say 'hat the rule does not permit to start this industry or that industry. That rule will only permit at places where the officers come from. Your officers are functioning in such a way that unless and until your offi.'cis just go along with the idens of industrial policy as enunciated by the Government of India, as indicated by the Prime Minister. Madam Gandhi you will never develop industries in our coun-" try because your officers are standing in " the way. Everything is a man-made manifestation. The' rules and regnla'ions arc framed by us. The rules and regulations are not born With' HS. We are responsible for creating the rules and Nearly 4 to 5 thousand' years back. we lust created so many tilings. The Britishers have made the rules and regulations. Everything is a man-made manifestation, as I just now said. Why do the officers stand in the way when you want to start an industry? I want a specific answer to this from our Minister.

Sir, as I told you already 'about this industrial procedure, even a small man cannot start an industry. What about the subsidy? Our State financial institutions are there. Before you give the subsidy, they just give an amount of loan to a person who starts an industry. But it cannot be reimbursed so easily. Even sometimes it takes two to three years. Who is to take up this responsibility? The person who starts an industry is not in a position to pay the interest. There is no use giving the subsidy to the State financial institutions until and unless this subsidy or the loan amount is reimbursed properly. Sir, now we give an industrial licence only upto Rs. 3 crores. Whenever anybody comes from my area or your area or this area or that area we just say that Rs. 3 crores is the limit. You go and start an industry. The industrial licence is not necessary. I think considering the cost of materials and the cost of starting an industry, it is better if it is increased from Rs. 3 crores to Rs. 5 crores.

Sir. so far T have dealt with the industrial procedures of the Government of India, how there is an inordinate delay, how the subsidy is not reimbursed properly, how the bridge loan is not reimbursed properly, and how exactly they started industries before 1967, how our State Government spent money-nearly Rs. 859 crores—thereby creating employment opportunities for more than a lakh of people. Now. 1 will mainly discuss about my Tamil Nadu Stale.

Sir. so many times, on the floor of this House, we have raised the question about the integral coach factory. An answer was given by our Minister just a week back here. Why I want to stress is that unless the haby cries, the mother will not feed her. Unless we ask very often, we will not be in a position to get it and you will not be" in a position to remember

it. sir. the cumulative out-turn of the Integral Coach Factory is more than 13,974 coaches every year. And the total estimate of the project is 70 crores. And the total value of the export order execut ed so far is Rs 25.57 crores. We have ex ported coaches to Burma, Zambia, Uganda and to so many countries. It is a very big Government institution. Nearly 3,000 *to* 4,000 people are working there. It has made a very good name. There is a very big popularity for this institution. We have exported to so many countries. Why should we not expand it? Why should we not start a second coach factory at Perambur whereby we can create em ployment opportunities to more than 5,000 persons. Why should we bring it from the southern corner to the northern corner where we have numerous industries now" Sir, I know fully well that I anr a citizen of India. I know that in 'he .Indian Constitution there is only one citizenship. There is no dual citizenship. I am a citizen of India. T cannot say that I am a citizen of Tamil Nadu Even as a man who is coming from that part of the country, I say, we beg of you to kindly expand or start the second coach factory at Perambur but not at any other place,

Then. Sir. what about the Salem Steel Plant? How much have we spent so far" is it Salem Steel Plant or Salem Steel Rolling Mill? Sir, we wanted to produce 32,000 tonnes of stainless steel. We have spent another Rs. 1600 crores so fur. Nearly 1,500 people are working there. What are we going to produce? There was an application from the Government of Tamil Nadu to double the capacity of the plant by installing a second unit at an estimated cost of Rs. 50 crores I do not know exactly the stage at which the matter is at present and what action the Government of Tndia is going to take with regard to that particular stage. What about the expansion of the Heavy Vehicles Factor) at Avadi? Sir, for the manufacture of modern battle tanks at Tiruvalhir, we had sent in an application. For Tiruvallur we have sent an application. Out of MS applications which are pending with the Government of India, this is one of the very important applications and we have asked so many times and we have approached so many times for a modem battle tanks factory at Tiruvallur. I want to know what the fate of this application would be. The State Government also wrote about the expansion of the Madras Fertilisers. I do not want to say more things about the Madras Fertilisers I have received an answer only today saying that since we are not in a position to get sufficient water in Madras, expansion of this industry is not possible. Now, Sir. We have ample water. We have water for three *more* years and with the blessings of Vsrina we will get more water. Therefore, Sir, I request you to expand this industry and see that the manufacture of modern battle tanks is started as early as possible. *(Time bell rings),*

Then, Sir, there is another problem. At the beginning I have said that we had 35 crores of population in the year 1947. Now we have 72 crores of population. Our hon. Minister should kindly listen to what I am saying. I am not going to criticise the Government of Tndia because by ciilicising the Government of India; the regional parties will not definitely get anything. That I know. We had 35 crores of population in the year 1947. but now we have 72 crores. We are now feeding 72 crores of population and every year we are expected to feed additionally the population that is the population of Australia. Every year we feed one Australia additionally. Next year one more Australia. Like that we are expected to feed the large growing population, more than 75 crores of population. I understand the difficulties of the Government of India. But what my point is and what my criticism is about the Government of Tndia. i.s that when they spend crores and cioies of rupees they think of us not as the citizens of India but they think of us as the citizens of the State from which they come from or to which they belong. Please do not think that we are not citizens of India or that we are tbe citizens of Tamil Nadu or Andhra Pradesh or this or that Srate. I do not want to name the State of the hom. Minister.

Except that one State I cam mention the names of all the States. But please do not think that we are not the citizens of Slates. We are the citizens of India. That is to say that when we spend crores and crores of rupees, we have to spend for the development of this country from Kanya-kumari up to Mount Himalayas.

What about the industrial districts? I told you already that for the past 17 years there is no Central Government investment in Tamil Nadu. There were 11 industries started before 1967 when my State was ruled by the Congress Government. After we came to power in the year 1967, for the past 17 years, the Government *of India* did not come forward to start even a single industry. When we . think that Government of India is ours when we think that we belong to the Go-vernment of India when we think that the entire amount for the industrial development of the country is our money, our national money, then you could spent some money for the development of my Slate. But you have .not started anything in my State. You have not selected even a single district from Tamil Nadu as No Industry District. You have selected 131 districts in the whole of this country from the sacred shores of Kanyakumari up to the tips of Mount Himalayas. You have selected 131 districts but you have not been able to find even a single district in my State which can be branded or considered or cited as a backward district. Do you mean to say that alomost all the districts in my State are very, very forward districts? Did you ever go to the corners of most backward districts like Ramana-fhapuram and other places where people are searching for water, searching for food, searching for livelihood? Even though they want small industries help from the Government of India, they are not in a position to get it. You can find poverty in almost all the States but in one particular State, in our State, not even a single district is branded as or considered or cited as a No Industry' District. I v,ant to know the. exact reasons for this. If you are not in a position to find even one district as a backward district, kindly hereafter sort it out on a taluka basis of block basis.

What about free trade zones? And thank you very much Mr. Minister for having cited my area for starting free trade zone whereby we had to give 15ft acres, now 200 acres more and thus 400 acres for starting free trade zones and sick industries. It is a very important question; my friend, Mr. Jain, was pointing out certain things with regard to Maruti motors. I too appreciate it that it was nationalised; And I suported it. \We have to nationalise this industry, had said. Now it has come out with flying colours. Even the Members of Parliament are itching for Maruti cars. That was the statement of Mr. Jain I agree with him and I supported its nationalisation. But I want to ask one-question, Mr. Jain. We have our B & C Mills. There are 15,000 people working there and they are not on strike for the past 6 to 7 months. I do not go into the merits or demerits of the problem. The finance Minister knows fully about this mil!. £ agree things are mot alright there; I agree, commercially it is not alright; know it. But let us consider the lives of 15,000 people and if you include their families, the number comes to 50.000. Is it not the duty of the Government of India to take up the entire responsibility to see that these 50,000 persons could live a peaceful and smooth life? Of course, there may be some defects. We have to incur certain losses. But do you mean to say that oil the Government of India undertakings are awning on profit? I request our Industry Minister and I. in-' directly, request our Finance Minister who can spend crores of rupees for the development of sick "industries, to take over the responsibility and start the Mills also.

Then I come to lado-French Textile Industries. There are 7,000 persons working and they are also on strike. Something has to be done for this Indo—' French textile industry at Pondicherry.

What about the textile industry? Next to agriculture and next to industry, comes the textile industry. Nearly 2.4 lakh people in the Southern region are completely depending upon this industry; they are working there. Not only, 2.64 lakh people work there, they consume 28 lakh bales of cotton. Mills in the Southern region produce over 1300 crores worth of yarn; that amounts to 33 per cent of the total yarn production in the country. What I request is, there should be reduction in the high incidence of duty on viscose. 6 fibre because cotton prices have shot up from 17 to 27 per cent; then we want reduction of excise duty on fine and superfine cotton yarn, and incentive for export of cotton yarn. These are the three things we have to consider for development of textile industry.

I do not know why Tamil Nadu has such a place on the map of India. Neither it has got water, nor it has got cower. In Delhi, you have water in abundance; you have power in abundance. We have no water and no power. For power, we should have our thermal stations. Or at least we should have coal. Neither we have coal, nor we have water. Water Is given by God; coal is given by God of West Bengal. There should be some steady supply of coal from other parts of the country to our State, and I request the Industry Minister to take up the responsibility for sending coal, that too good coal. Forty per cent of the coal Is in had shape. You kindly see that coal is sent from other parts of the country to our State. .(Time *bell rings)* T am just concluding. I have to so to Madras and I will finish in two minutes.

Then, expansion of Arivalur cement plant has to be taken up. We have asked for it so many times. A new cement plant at Palavam in Madurai has to be set up . Application tor this cement plant should be considered.

Photo-film plant you cannot give and we cannot get because it has already been taken to Nainital, it seems. We cannot get that.

Finally, Neyvelly third mine cut project should also be taken up during the Seventh Five Year Plan. '

I thank you for giving me this opportunity and I also thank the Minister for giving permission for a free trade zone as well as for starting Leather Promotion Council, especially at Madras. With these words, I conclude.

SHRI SANTOSH KUMAR SAHU (Orissa): Today when we are discussing about industrial development of the country, it is definitely true that there has been so much of progress from the beginning of the First Plan till today. Industrial production has gone up 5 times since 1951. Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India laid the foundation of the major industrial policy in this country so that major and key industries are established in the public sector. We are proud today that many of the basic and key industries have been set up in the public sector.

The Industrial Policy Resolution adopted by Parliament in 1956 has laid down the basic principle for industrial development in the country the pattern of development, the role of the public sector, the private sector, the small-scale sector and so on. We should also remember that the framers of the Constitution had also the same idea when the Constitution , was drafted. They enunciated the principle that the concentration of economic power in a few hands should be discarded. These are the main guiding principles behind the Industrial Policy Resolution and for the industrial development in our country.

When we discuss the industrial policy the main question which arises is, the incidence of population on agriculture and how it can be broueht down. Many hon. Members have pointed out that though there has been industrial expansion, the incidence of population on agriculture has not come down. There are also other factors which arc responsible for this. The brisk point is the population has increased mani-fold. This is one of the reasons why, perhaps, in spite of successful indus-

(shri sancosn Kumar sanuj

trial expansion, we have not been able to decrease the incidence of our population on agriculture. But at the same time, it creates a new thinking process. It makes us think as to what we should do about it. It raises the question as to what we should do in the industrial sector so that sufficient employment opportuuities are generated, for the young and educated men. With this end in view, the Prime Minister announced a new programme for the employment of educated youth. The hon. Minister for Industry has also said about this in the Consultative Committee meeting yesterday. I was reading from the papers. As per his statement yesterday, 2,18,000 unemployed educated youth have been given financial assistance by the banks to establish new industries. This is a new saga. This is a new type of approach. Earlier, the financial institutions were giving loans only on the basis of security. Now, the

stress ij on development of new entre-preneurship. This is a new type of vision. The principle for this has been laid down.

There are two other important things in this connection which I would like to mention here. This has been discussed in the House many times in the past. One is about regional imbalances. Removal of regional imbalances is very

important if we have to have lall-round development. We should also develop the backward areas. Many of the economic thinkers and planners are going into this, how to bring about industrial development in these areas. When we see the repot of the Ministry of Industry, we see that they have laid down the principle for identification of no industry disHqts. They have categorised them, A, B. C, This is mentioned in para 4 of the Report of Industrial Development j Department (1983-84). They have also men'ioned about various things like special assistance, subsidy and so on. | Though we have progressed very much. I would point out to the hon. Minister \ that in the silver sky, there are some patches of dark clouds which we have to remove. We have to restructure and bring about a very dynamic industrial policy to fit in with the needs of the modem times.

Sir, in the beginning of the First and Second Five-Year Plans, our policy was to substitute imports. Now, the stress is
on the fact that we should have more export-oriented industries. For this, we-have to rake new steps. What arc thosa steps? When We talk of exports, India is at a very adventageous position, for the development of export-oriented industries. We are the third "largest nation in the world, as far as trained, technical manpower is concerned.

If the energies of these people can be harnessed in the proper development of industrial growth, then naturally we can compete with other countries, and there is no doubt about it. Government has undertaken definite steps to reorient our industrial programme in that direction.

The second advantage with us is that labour is comparatively cheaper in our country than in the developed countries of the world. If we examine the industrial development in the whole of the world. we see that if one of the factors of production is cheaper, then the developed countries cannot compete, if we have the will to work and technical know-how. So it is very important that we should restructure our industry in such a way that we can compete with them. So that is one of the very important questions which must be looked into nowadays for development of the industrial sector into a viable competitive sector in the modern world. India is leaping ahead and I hope it will go still further and it will be one of the major leading industrial countries someday if we move in the right direction.

But I must also point out what the difficulties are in our way. Time is a vcy important fector in industrial development of any country. Unforlunately in our country the gestation period for staling an industry, getting through all the procedures and establishing it, take a

long lime which must be curtailed. The industrial culture which has developed in developed countries is one where the entire infrastructural facilities can be easily made available to a young entrepreneur. If a technically qualified man comes into industry, it might be a small industry, all the group infrastructural facilities must be given to him within a short span of time so that it will give a lot of encouragement. This is one of the procedures which is under review. It has been reviewed by the Industrial Development Committee, but it requires a still further review and straightening of procedures so that unnecessary delays may be curtailed.

The second aspect and the most important 'aspect of what I have referred to ag the "dark clouds" is the sick industrial units, in which, according to the Reserve Bank of India Report; Rs. 2.229 crores were locked up upto June 1982, consisting of large, medium and small units. 435 large industries, 1119 medium industries and 2673 small industries were in the sick list. According to a survey of a study team, many of the large industries will be made viable if there is more financial assistance available and some managerial input developed). Fifty per cent of the small scale sector is not viable. Another study has revealed that 48 per cemt of the large scale industries are suffering losses due to managerial inability. So it is a vital question. If we want to build up a very strong industrial culture in this country, the managerial aspect, the entrepreneurial aspect must be looked into.

Another important factor which I would like to put before the Industry Minister through you. Sir, is that there is *a* geographical sliift of the industrial locations in spite of all our attempts. Thirty years ago, Calcutta in the eastern sector was number one industrial city in the whole of the country. Now if is no more. Now the critics divide industries into two categories: one is the sunset Industry and the other is the sunrise industry. Add the golden belt of industrial concentration goes from Ahmedabad to Baroda to Bombay, Poona and Bangalore. Of course there are many pockets within these areas where there is no industry. But on the other side—i.e. in the eastern side of India—the geographical shifting of locations of industry has created many voids. Some steps must be taken by the Industrial Development Department to see how there also some new industries can be set up which will help in employment and regeneration of the economy of this country. Sir, sometimes when we study economics report[9] we see many thing, which are very vital for the development of industry as well as the nation. Economic critics say that even steel has become a sunset industry . all over the world. In India it is kept alive through a regular injection of price-rise, but at the cost of the consumer. Hiey say that after five or ten years it may become an inefficient steel industry and sick steel industry. So, what they have done in the developed countries is "-that they have restuctured the industry. So, Sir, while faying a firm policy for the development of new industries, we must remember that this aspect needs' constant study and industries need restructuring without which, probably our" whole industrial development will be jit' jeopardy. So, it is the need of the hour; it is a question of "Restructure or Perish." This is a very fundamental question to which I would like to draw the attention of the hon. Industry Minister.

About backward areas—I am speaking specially of States like Orissa—my own State —and some such other States. Though the Government of India is very much interes'ed that the backward areas must develop, I would like to emphasise here that the Industrial Development Department must see that more emphasis is given to this sector Nuclear projects may be started in the backward areas after surveying the growth of Industries in the different sectors. It will stimulate improvement in these areas, secure balanced development and help in the removal of regional imbalances.

Now, another important factor, though it is very much fclien to the subject, is the failure in the power sector

[Shri Santosh Kumar Sahu]

in our country. There is no point in concealing the fact that many of the big industries even in the public sector had suffered loss of production because of power shortage in the previous years. So, we have to take some pragmatic view of how in future we can develop these industries with captive power projects or .have sufficient power So that the industrial loss which has gone up to Rs. 12,000 crores in the year before can be curtailed. Othtrwise the industrial sector will be in great difficulty. Therefore, greater coordination is required for the development of the power sector too.

Sir, I was reading one of the industrial economists' comments. He mention-be one very, very fundamental question which is applicable to India also. He says "it is an illusion that we can industrialise a country by building factories. We do not. We can industrialise by building a market.' That is ColeHoffmann. This is especially very true of our small-scale sector which I will analyse here. The Government of India and the State Governments are emphasising very much on the developmnt of the small-scale sector. But there is no proper market study, no market intelligence. The bigger blouses never support the small-scale sector until their interest is served. Even the public sector undertakings which are located in *the* backward areas never support the small-wale industries which are in the local areas and this creates a great problem to them. So I think we should take a very definite and strong attitude to encouracp them. Otherwise many of the young entrepreneurs who had started small-scale innvstries would be suffering and that will not help in the industrial development of the country. There must be positive steps taken for industrial development in this sector in that the public sector under-takings or large industries must try to give preference for the purchase of Pro' ducts of the small-seal,, sector of the local areas first and then only go to other markets—without which the backward areas will remain backward and young entrepreneurs of the small-scale sector Can never expect to grow because of this great problem. So, all through the world it is accepted that without developing proper market facilities, the small-scale sector which has no economic power nor . the power of advertisement cannot take advantage of all these schemes. In our country, for better employment of people the development of the small-scale sector is a must; we cannot neglect it. Sir, I will give you one example, though it is not directly related with in dustrial development. If we go through the reports for the past ten days in the Times of India, we find mention of the heavy water project at Talcher in Orissa which was to function from 1976. Now it is 1984. The economic studies made by the Times of India reveal that the men who managed at the beginning created confusion and there have been defects. And those men *have* been promoted. Now other people have come. You require more money. In how many years finally production will come up, God alone knows. So the lesson is that for streamlining the public sector under takings there must be accountability of the higher officers in any public sector undertaking so that they will be accoun table for their lapses and timely com pletion of the projects must be achieved to. That is one of the most important things. . -.- ..

Then, in this world, when we are having severe competition among different countries, the cost factor is very vital. The industrial sector has a scheme for it, but it must be very pragmatic and realistic. *{Time-bell rings)* One or two minute* more.

Research development is one of the very fundamental things. The Government must take keen interest in it. Not only that. We find many industries running sick—like jute mills, textile mills. Probably the management does not look into the demands for proper research and modernization. Why not make research efforts? For research there must be sufficient money out of the profits.. They take money, siphon it off to other industries for diversification, for greea pastures, to earn more. But the Gov

ernment has to pay through its nose to keep up employment of the labourers and run the sick mills. It is fundamental throughout the world that they give a lot of emphasis to research and development. In America, every company has a programme of research and development. If we have to compete, we have to think about research and development.

Another factor which is important is, in Japan, which is one of the leading nations in Asia in industrial development they develop not one industry like steel only but they have plan to have chain of industries, so that the cost is reduced. For producing one thing if they want fuel of a high temperature, they produce the high temperature, afterwards the lower power is utilised for certain other industries. Like that we have to think of new innovations.

Lastly, I would urge upon the hon. Minister to think of restructuring and to have a dynamic industrial growth, we have to think of technological development, give more emphasis to research and the small scale sector. That is the crying need of this country today. Restructuring of the sun-set industries which have no hope of development and which are suffering today should be thought of immediately, not after five years. Otherwise, the industrial expansion that we have will be in danger soon. Adequate employment scheme announced by the Prime Minister must be pursued so that young entrepreneurs in every nook and corner of the country come up. They must be given all the technical know-how knowledge about projects, and not financial assistance alone, so that there is cluster of industrial growth, because we have the technical manpower.

With these words, I thank you and hope that the Industry Minister, who is a very dynamic man will take some decisions on the aforesaid matter and help the country for better industrial growth.

SHRI SURESH KALMADI; Mr. Vice-Chairman, Sir, I must at the outset say that our Industry Minister, Mr. Tiwari has been putting in a lot of effort in his Ministry. But he must be wondering why he is not able to produce results. It is primarily because the policies have been lopsided. He must ba wondering why the industrial growth is not more than 3 per cent in spite of all his best efforts. The answer is very gim- ple. There has heen a lopsided growth of the country's industries in the last four years. And what I am worried about is the industrial growth rate is lower in the eighties than it was in the seventies; the industrial growth rate was lower in the seventies than it was in the sixties.

And the industrial growth rate was lower in the 60s than it was in the 50s. And I do not know when we will get back to the industrial growth rate of 7 per cent which was there in the 50s. There must be fundamental changes in the snapping of the industrial policy for the Seventh Plain, and I am sure, i£ this is done, then, our growth rate can bo brought back to that in the time of the 50s.

The public sector, we all have been hoping that it will be a model for many countries. But, unfortunately, the public sector has not functioned efficiently at all. As a matter of fact, many units are losing. Bad management, political considerations have outweighed business considerations as far as the public sector is concerned. We must change this in tlw Seventh Plan. We must ensure that the ' public sector units should be well run units. The best managerial talents must be inducted into the public sector units. Their heads must be appointed at the earliest. I never understand how, and I came to know, that 20, 30, 40 0/ the public sector units do not have proper heads. Somebody is acting on their behalf. How can you do it? You have to run them like the private business. I 1 think the Government must consider how we can induct the best talent, the cream of the managerial skill, into the public sector. The units which are perpetually losing in the public sector must be turned into joint sector projects in the Seventh Plan. This major policy decision must be taken.

[Shri Suresh Kalmadi]

Also, [he need for infrastructure is very essential. We have not paid enough attention to coal; we have not paid enough attention to power; we have not paid eaough attention to the railways. There must be higher investments in these core sectors. You are aware, Sir, that as per the Mid-term Appraisal of the Plan, the electricity generation is expected to be no more than 170 billion units against the target of 190 billion units. The power shortage alone is going to cost the nation, going to cost the industry, a loss of about Rs. 10,000 crores, per year, on account of the power situation alone.

In the very first year of the Seventh Plan the repayment of the IMF loan will start. So, it is very imperative that our whole accent must now shift on export-oriented industries from heavy industries. This is very clear.

To day I would like to concentrate mostly on the industrial licensing policy and the removal of the controls. Sir, many felt very bad when Mr. Tiwari on 22nd of March in the Rajya Sabha announced that there would be no baste changes in the industrial licensing policy. I do not know how he made this statement because Just in the beginning of the year the Government had appointed the Narasimhan Committee to go into the licensing policy. Now with the statement of the Minister, I think, the whole Narasimhan Committee exercise is nothing but a sort of deception. Earlier the Government had constituted the Dadri Committee, and that recommended scrapping of many controls. But that also is gathering dust somewhere. All the *netas, babus* and vested interests in industry have been very keen of perpetuating the licensing system.

I shall just read out the number of licences that a person has to obtain before he can start an industry or expand *bis* existing industry. He has to first get the industrial licence under the Industries Development and Regulation Act, 1951, the capital goods import licence under the import control policy; the approval of the foreign Collaboration Board, approval of the Foreign Investment Board, approval under the MRTP Act, the approval from corporate bodies under the Capital Issues Control Act, the approval under the Companies Act, 1956 and so on and so forth. Obtaining the industrial licence is only the starting point of a number of other approvals he requires not only from the Central Government but also the State Governments | and still later from various financial i intitutions. Well, the licensing policy was initiated many years back by late Pandit Jwaharlal Nehru. It has its role because the capital should be diverted to priority sectors. I am sure in the first 20—25 years we have created a capacity in our heavy industries. It was a very good thing. The licensing system in the country has definitely brought rich dividends. But today a time has come to reconsider whether we continue to require licensing or not. It has created shortages. Even Shr; L. K. Jha who is the Economic Adviser in the Economic Reforms Commission himself said in his various articles and even in hi, book that the licensing system in the country has got shortcomings. Even in my own State, Mr. Jagesh Desai—you know about the cement control what havoc it has caused. How the politicians utilised these thinss to their advantages? *(Interruptions).* The-politicians have made the use of the licensing sysem to make money. It has created shortages. You know very well how the Government has utilised the licensing system to make money. T would have been happy if the licensing system so introduced would have been used for import of fertilisers and medicines The import duty has not been slashed on these items on what items import duty has been slashed? The import duty has been slashed on motor cars. Today Maruti is importing cars. The duty has been brought down from 160 per cent to 40 per cent.

Similarly the Fiat and the Hindustan Motors have been given concessions. This i» the priority of our present Government. Today, we have large capacities to manufacture two-wheelers in our country. We have Bajaj Auto Lfd.,the second largest

manufacturing two-wheelers company in the world. But yet we are going in for foreign collaborations to start other scooter units. So this is our requirement. Was it required when the Piaggio itself challenged Bajaj Auto in the court of law in many countries of the world? *(Time bell rings).* I have just spoken for seven or eight minutes. The duty on colour T.Vs. has been brought down from 160 per cent to 40 per cent. This is the priority of our Government. It is not for the common man. This Government is for the rich, of the rich by the rich. This concept is manifested in your various policies. The foreign collaborations have gone up by 2 times in the last three years. Every day. Sir. you are signing two foreign collaboration agreements Out of 150 foreign collaborations which have been set up in last three months alone—hundred of these foreign collaborations are only in the State of Uttar Pradesh. This has been revealed by the Minister himself in one of his written replies which I will show you. THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): Mr. Kalmadi it is not 100 but 11 in U.P.

SHRI SURESH KALMADI; 1 am quoting the figure 100 in U.P. from the written reply you have given to us. Perhaps you might have rectified it later on. *(Interruptions)* .

SHRI NAARYAN DATT TIWARI: Out of 50 foreign collaborations, 11 have been set up in U.P. and 19 in Tamil Nadu. *(Interruptions).* There were only two supplementaries. *(Interruptions).* 6 P. M. -

श्री जे० के० जैन : अब क्षमा तो मांग लीजिये ।

श्री सुरेश कलमाडी : क्यों मांगूं ?

The written answer of the Minister is there. I can show the written answer. If the Minister has corrected it, it is a diffe rent matter.

I would also like *to* say about the abundance of foreign trade marks. It is the Government's policy not to encourage foreign trade marks. But what have we seen in the last three years? You have allowed a cigarette company, Duncan, to go in for Rothman's cigarettes. Was it required? Are not Indian cigarettes good enough? Are not Indian butter and cheese good enough? Did we have to' go in for the Marmite trade mark abroad even for these things? And what do they say? They say that as long as no foreign exchange is involved, they can go ahead and two . foreign trade marks. Do you mean to say that Duncan did not pay anything for the trade mark of Rothman's? They have paid money for it outside the country. Rothman's is not going to give its trade mark free. In the name of giving foreign exchange, a lot of money is being siphoned off to persons in other countries.

About non-residents, I am very happy with the various schemes that you have come up with. But I would have been happier if the money which has come in from non-residents had been put to use *to* set up new industries. That is what wo should have insisted on: yes, go and invest and start new industries. But the industries of people who have stayed in the country, who have put their sweat and toil in this country, are being destabilised. Non-residents are coming to this country, buying shares of well-run companies and destabilising them. How can anybody tolerate such a situation? I think clear-cut guidelines must be made for the investment of non-residents. It is very good to try and get their money, but it must be used la start new industries.

Also in the name of non-residents, you are aware, a lot of black money has been siphoned out of the 'country and it has come through various methods—Isle of Man, etc.-back into this country as white money from non-residents. Sir, I am surei you know about this. Also you are aware that there is a sword hanging over the industry today. Up to now, financial institutions never destablised good running companies. But to day nobody is safe, Financial institutions are destabilising good companies who cannot meet the demands of the Government, who cannot pay for the election funds. Then the Finance Directors in the various companies are made *to* talk and the moment they are made to talk the company come to terms with the Government. This is indeed a very bad thing.

The last point is about unemployment in the country. I am very sorry to say 'hat the employment target of the Sixth Five Year Plan, according to the admission of *the* Government itself, has not been achieved, and that the performance has fallen far short of the target. We have already 5 crores of unemployed persons and on the live registers of the employment exchangees, already 2 crores have been registered. There has been a fantastic increase in unemployment in the country and unfortunately the Goverment is not doing anything in the matter.

Than you are not at all insisting on the capital-employment ratio. Banks aro giving loans to many people, but. do you ever ask them how many people are given employment by them? There is no column in the bank form to show how much employment is to be given. You are not encouraging labour-intensive units. The moment somebody gets crores of rupees from you, the first thing that he does is to import machinery from abroad, to get as many machines as possible which will replace man power I am not against technology. Definitely wherever high technology is required, we must go in for sophisticated technology. But there are so-many industries like the forging industry and the chemical industry which are lab-out intensive industries. Why don't you place emphasis on these industries so that you can have more labour?

Also the small-scale industry has been totally neglected in the country and the whole situation in the country is in favour of big industries. If I have to start a mall-scale industry, I have to go to 28 different agencies to some place for power, to another place for money, to a third place for material. That way there are 28 agencies. It will be desirable if the Government can have one window, one place where the 28 agencies can sit together and a person can get everything sanctioned wilhm a month's time. If you do tint, you will have done a service to the small-scale industry All the repayment of loans and interest by the small-scale industries should start after the product reaches the market. What is happening today? You set up an industry or a unit, start borrowing from left, right and centre, and before you even start producing something, you are asked to return the money to the bank. Therefore, you should consider the suggestion that for small-scalo units you shall charge interest only when the product reaches the market, *(time-bell rings)* Then about the guarantors clause. You insist on producing two guarantors for the educated unemployed. If a person has to buy a truck he has to get two guarantors. From where does the educated unemployed get guarantors? Even as it is, the truck is hypothecated to the bank. Isn't it good enough? Why don't you scrap the guarantors' clause as far as small-scale industries are concerned? This is very important if you really mean to encourage imall enterpreneurs. If you want to give more and more to the big industries, I have no objection, but if you really want to give work to educated unemployed, you should give them meaningful incentives. You cannot do it just by giving mass loans to 40,000 people in the Ramalila Ground. It is not the way of developing small-scale industries. It should be done in a proper, calculated manner. With these words. I conclude.

SHRI YALLA SESI BHUSHANA RAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I think you for giving me this opportunity to participate in the debate on the working of the Ministry of Industry., It is true that industrialisation holds the key to rapid economic development. But industrialisation is not a bliss in itself unless certain imaginative and constructive, steps are taken to ensure that the resultant benefits reach the common man for whom they are intended. Mahatma Gandhi rightly stressed the need for rural, small-scale and cottage Industries, the need of the vast population of this rural India. But unfortunately Mahatma Gandhi has been forgotten, the philosphy of his economic development has been forgotten in this country, while other countries of the world are trying to take advantage of his philosophy of economic growth. India lives in its villages. The industrial policy of the Union Government, particularly

the Industrial Polity of the Union GOY-ernment, particularly the Industrial Policy Resolution of 1956, has been much talked about but in implementation there appears to be a large area yet to be covered. I urge upon the Union Government to avoid the mistakes committed in the past in the industrialisation of the country and to correct the regional imbalances and disparities in growth which have, in a way, contributed to and aggravated the problem of unhealthy urbanisation. The per capita investment in the public sector is Rs. 396 as on 31-3-1983 in Andrra Pradesh. That is, it is lower than the average per capita cumulative income of Rs. 467 in the country. Andhra Pradesh is an agricultural State. It occupies the third place with 8.4 TJer cent of the total foodgrain production fa the country. It is supplying one million tonnes of foodgrains to the Central Pool. That is why it is called *Annapoorna. in* addition to foodgrains, Andhra Pradesh produces mostly tobacco, sugarcane, cotton, jute and other agricultural commodities. It is, therefore, necessary that agricultural based industries are set up in the State. This alone will alleviate the sufferings of the farmers and eliminate the uncertainties they face. The licensing policy formulation and decision-making is mainly concentrated in Delhi. It should be decentralised. The Union Government has to raise the exemption limit of licensing to Rs. 5 crores or more for the middle level entrepreneur. The areas qualifying for Central scheme of investment subsidy in backward districts of Andhra Pradesh have to be further surveyed so that more genuine and needy* areas get included in the schemes. For example, Srikakulam district is considered a backward district after the State Government formed a new district named Vizia-nagram; a maior portion of the area in Srikakulam district and some taluks in Visakhapatnam district have been carved out and formed into a separate district. Unfortunately the areas that were under the backward scheme of Srikakulam district have been carved into Vizianagararn, district and the benefit of the backwardness of these taluks is lost. I would request the Government to consider Vizianagararn district of Andhra Pradesh also as a backward district for purposes of subsidy *ot* the Central Government.

There is a large scope to develop salt manufacture and to start coir industry in Srikakulam area. There is vast growth of jute in Vizianagararn district. There is neej to develop jute factories there There is much talk of grant of licence for jute factory in Salur. But up til! now it hat not seen the light of the day.

Vishakhapatnam has got huge potential for industrial development in view of its location and its natural harbour. Large deposits of bauxite are available in the east coast of Andhra Pradesh and the State Government is pressing the Centra to set up an aluminium project in this district. The State Government have confirmed the availability of 2,433 acres or land for the purpose and the State Government has also reserved bauxite ore bearing areas for exploitation in the public sector.

There is an investigation and study re port by Soviet experts and Bharat Alu minum Company which is still under the consideration of the Union Government. I would request the Hon'ble Minister to give us an assurance that it will be taken up in the next Plan.

There is lot of scope for ceramics and graphite industries in Andhra Pradesh and the State Government has been urging the Union Government to take steps to provide assistance in this matter also.

Sir, this is the age of electronics. TTiere is need for industrial and consumer electronic goods. Andhra Pradesh Government has been persuading the Central Government to set up a prototype development and training centre for electronics at Kushiaguda near Hyderabad by the NS1C. There is a large number of electrical engineers who are competent to learn and do the work. T would request the Hon' ble Minister to consider this immediately.

The .Prime Minister of India, Shrimati Indira Gandhi, in all her wisdom has emphasized that there should be no project delays and delays will lead to cost escalation. I will give an example about Vizhakhapatnam Steel Plant. The iteel plant

[Shri Yalla Sesi Bhashana Rao]

was sanctioned after years of agitation and sacrifice. There has been little progress in its completion. The Andarh Pradesh; people are anxious to see that the first stage of the project is completed within stipulated period of three years. The budget allocation for 1984-85 is only Rs. 4R0 crores for this project as against a total expenditure of Rs. 4,100 crores. The amount spent so far as only Rs 1,000 crores. For three consecutive years. for each year, an amount of Rs. 1,000 is required as per the programme scheduled. As against that, for the present there is only an allocation of Rs. 480 crores for this year. Half the amount will be spent on civil works. The balance is not enough for the machinery ordered and the authorities had to pay demurrage as they could not take delivery of the goods in time This grave situation faced by the steel plant has to be considered and I would request the Prime Minister not only to talk of delays, but to act in this case immediately,

I said just now that Andhra Pradesh is an agricultural State. It needs lot of fertilisers and there is a proposal to set up a fertiliser factory at Kakinada. The Central Government has to issue indents and licences. Likewise, the tyre project at Manglagiri in Krishna district is also pending with the Central Government.

Sir, I humbly urge upon the honourable Minister of Industry to act immediately to satisfy the just demands of the people of Andhra Pradesh. I also suggest to the honourable Minister to send a team of ex pects to Andhra Pradesh to identify the most promising and potential industries "based in local resources and to formulate schemes and to start action programmes so that whatever steps have to be taken by the Governments, the Central Government .and the State Government can be brought over and this would be more useful for making Andhra Pradesh more indusjria-Jised. ,

Sir, with these few remarks, I requet the honourable Minister to ponder ove these matters and consider the just demand! of Andhra Pradesh.

Sir, there is a dynamic Chief Ministei there in Andhra Pradesh and there is alsc a dynamic policy laid down by the Government of Andhra Pradesh with Shri N. T Rama Rao at the helm of affairs. 1 request the honourable Minister of Industr) and also the Central Government to for mulate much needed schemes immediately and co-operatg with the Andhra Pradesl Government to develop the agricultural State of Andhra Pradesh and put it on the industrial map of India. Thank you. Sir.

श्री रामेश्वर ठाकुर (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्रालय की इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे जो सुअवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं विशेष आभारी हूं । उद्योग मंत्रालय के सन् 1983–84 के प्रतिवेदनों से प्रतीत होता है कि देश की आधारभूत सुविधाओं में, खास तौर से ऊर्जा में कमी होने के बावजूद, अन्य बाधाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा होने के बावजूद भी उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय नीति, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो कार्य उद्योगों के विस्तार एवं उसके प्रसार के लिए किये हैं वे अपने आप में सराहनीय हैं । मैं इसके लिए माननीय उद्योग मंत्री जी को, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को तथा देश के विभिन्न भागों में उद्योगों के कार्य में लगे हुए लाखों मजदूरों, व्यवस्थापको, तकनीकी लोगों को और दूसरे अन्य लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं । सन् 1983–84 में उद्योगों की दिशा में साढ़े चार प्रतिशत की अभिवृद्धि हुई है जो सन्

1982-83 में 3.9 प्रतिशत थी । देश की बढ़ती हुई आबादी तथा साथ साथ जो हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए यह जो हमारी अभिवृद्धि की गति है वह कम है, ऐसा हमें प्रतीत होता है । देश में विकास की जो क्षमता है, आधारभूत जो सुविधाओं को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, हाल में ऊर्जा के क्षेत्र में, इस कर खनिज तेल के विकास में जो सफलता मिली और आगे जो 30 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है उनको ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा लगता है कि आर्थिक दृष्टि से इसी सीमा में कुछ मुद्रास्फीति के होते हुए 23 प्रतिशत की बचत आंकी गई है, यह हमारे लिए शुभ चिन्ह है । हम समझते हैं कि आर्थिक विकास का 10 प्रतिशत का जो लक्ष्य रखा गया है वह लक्ष्य संभवतः हम शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं । इसके लिए आवश्यकता है निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को इसके लिए दृढ़तापूर्वक विशेष प्रयास करना होगा जिससे हम शीघ्र से शीघ्र इस 10 प्रतिशत के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें । हमें जो उद्योगों की विरासत मिली है उसके भी जरा समझने की आवश्यकता है । यहां पर कई मित्रों ने और खास-तौर से हमारे विपक्ष के जो मित्र थे, जिनमें अधिकांश यहां से, सदन से जा चुके हैं उन्होंने शिकायत की कि जिस तरह से उद्योगों की स्थापना की गई है इसका संबंध क्या देश के विकास से है । मैं कहना चाहता हूं कि हमें विरासत में जो उद्योग मिले थे, आजादी के समय, यह हम सभी जानते हैं, कि हमारे यहां पुराने समय में सदियों तक हस्तकला और दूसरे गृह उद्योग थे, वे सब के सब ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन काल में 1747 से लेकर 1858 के बीच, लगभग सौ वर्ष में ह्रास हो चुके थे । लगभग सौ वर्ष, 1958 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों का जो शासन काल था उसमें कुछ उद्योग खासतौर से निजी उद्योगों की स्थापना हुई । एक सूती मिल और एक जूट मिल की स्थापना 1850-55 के बीच में हुई । उस समय मात्र एक रेल लाइन की स्थापना हुई । लेकिन ब्रिटिश काल में जिन भी उद्योगों की स्थापना हुई उनकी दशा यह थी कि इनके द्वारा ब्रिटेन को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और यहां का शोषण हो सके । यह मानी हुई बात है, ऐतिहासिक बात है । उस विरासत से, 1947 के बाद सबसे पहले 6 अप्रैल, 1948 को हमारी औद्योगिक नीति की घोषणा तत्कालीन लोकप्रिय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की । जिसमें कहा गया था कि एक सार्वजनिक क्षेत्र होगा जिसका एक विशेष स्थान होगा और दूसरा निजी क्षेत्र होगा । लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुभव के आधार पर 1956 में इस पर विचार फिर से हुआ और द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा की गई । 1956 में देश में उद्योगों के तीन भाग रखे गये । इसमें यह था कि देश में एक श्रेणी में केवल सार्वजनिक उद्योग हो, बी में निजी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग दोनों हों और सी में निजी उद्योग हों । थोड़े से परिवर्तनों के साथ, वही नीति आज भी हमारी औद्योगिक नीति की आधारशिला है । हमें देश को शक्तिशाली बनाने के लिये, देश को सुदृढ़ बनाने के लिये, देश में अधिक रोजगार मुहैया करने के लिये, निर्यात बढ़ाने के लिये, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने के लिये और साथ ही साथ हमारे देश में मूल्यों में जो वृद्धि हो रही है, उसको रोककर उचित मूल्यों में अधिक से अधिक लोगों को और खासतौर से कमजोर

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

वर्गों और जो गांव में रहने वाले लोग हैं, करोड़ों लोग हैं उनको उचित कीमत पर सामान मुहैया कराने के लिये आवश्यक है कि हमारे उत्पादन की गति कम से कम 10 प्रतिशत बढ़े और इसके लिये हमें अवश्य ही इस तरह का प्रयास करना चाहिए ।

महोदय, माननीय मंत्री महोदय को इस दिशा में मैं कुछ थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं । लेकिन इस दृष्टि से नहीं कि सरकार के द्वारा जो विभिन्न कार्य हुए हैं उनमें क्या त्रुटियां हैं। मैं सुझाव इस दृष्टि से दे रहा हूं कि यह एक दिशा है जो प्रयास हुए हैं । हमारी आवश्यकताएं अधिक हैं । हमारी आबादी तेजी से बढ़ रही है । इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि हमारी जो मूलभूत नीतियां हैं हम उनकी तरफ ध्यान दें और अगर उनमें कुछ त्रुटियां हैं तो उनको हम दूर करने के लिये विशेष प्रयास करें ।

मेरा पहला सुझाव है यह कि देश की भौतिक सम्पदा और मानव शक्ति का समान विकास हो । राष्ट्रीय हित में यह नितान्त आवश्यक है । देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मानवीय मूल्यों का बहुत बड़ा स्थान है । जिस तरह से कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में इनका पालन किया था, उनका समावेश किया जाय और उन्हें वरीय स्थान दिया जाय ।

मेरा दूसरा सुझाव है कि देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिये स्वदेशी की जो एक हवा थी उसे हर स्तर पर लाने की आवश्यकता है । इसके लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधार जो देश का है उस को ध्यान में रखते हुए हम उद्योग के विकास के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करें ।

तीसरा सुझाव है कि आपने हस्तकला और ग्रामीण उद्योगों को बचाते हुए, बढ़ाते हुए तकनीकी और विज्ञान की ओर हम तेजी से अग्रसर हों क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अन्य विश्व के देशों से मुकाबला करना है और तेजी से आगे बढ़ना है । इसके लिए जो हमारे तकनीकी विशेषज्ञ हैं, विज्ञान के क्षेत्र में शोध करते हैं उनके शोध के लिए, प्रशिक्षण के लिए न केवल छोटे और बड़े लोग जो उद्योग में आते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, बल्कि अन्य लोगों—मजदूरों, कारीगरों, व्यवस्थापकों, वित्तीय सलाहकारों, लेखाकारों और दूसरे जो व्यवस्था में लगे हैं उन सबको उचित स्थान, उचित प्रोत्साहन मिलना चाहिये जिससे कि वे समझ सकें कि उद्योग के विकास के वे भागी हैं और उसका लाभ उन सब लोगों को उचित रूप से मिलना चाहिये और वे अपने आप को उद्योग के विकास में साझीदार समझ सकें ।

चौथा सुझाव यह है कि जो आधारभूत सुविधाएं हैं जैसे ऊर्जा का सवाल है कोयले, खनिज का सवाल है, रेल यातायात, आवागमन, संचार आदि की सुविधाएं हैं, देश के विभिन्न भागों में समुचित रूप से उनका विकास किया जाए तभी विदेश के विभिन्न भागों का उचित रूप से दोहन हो सकता है ।

मेरा पांचवां सुझाव है कि देश की उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है । हम अंग्रेजी के शब्द व्यवहार नहीं कर रहे हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जब हिन्दी में कोई आदमी बोलते हैं तो अंग्रेजी के शब्द उसमें लाते हैं इस लिए मैं अंग्रेजी के शब्द इसमें नहीं ला रहा हूं । इससे कुछ सदस्यों को समझने में दिक्कत होती होगी लेकिन मैं जानबूझ कर हिन्दी के शब्दों का ही व्यवहार करना चाहता हूं । जो हमारी क्षमता पिछले

25–30 वर्षों में बनी है उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है । उससे बहुत से विकास के कार्य हो सकते थे क्योंकि उसमें रुपया लगा हुआ है, साधन लगे हुए हैं । नयी क्षमता हम जरूर बढ़ावें लेकिन जो क्षमता अभी बनी हुई है उसका पूर्ण विकास कर सकें उससे हमारे उद्योग की आधारशिला मजबूत होगी, उत्पादन बढ़ेगा और उसका लाभ देश को मिलेगा । मेरा छठा सुझाव है कि देश में कार्यक्रम से बहुत से छोटे, मध्यम और बड़े उद्योग रुग्णावस्था में हैं । उन में सरकार का खास तौर से वित्तीय संस्थाओं का, बैंकों का बहुत रुपया लगा हुआ है । लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं । यह राष्ट्र हित में है कि ऐसी संस्थाएं तकनीकी दृष्टि से जिनका विकास हो सकता है उनकी छानबीन तेजी से कर के बिना विलम्ब किये हुए और जो संचालक थे उनकी सुविधाओं या उन्हीं के प्रयास से, बिना रुके हुए, राष्ट्रीय हित में आवश्यक है उसकी तकनीकी जांच करने के बाद यदि उसको क्षम्य पाया जाए तो उसका विकास तेजी से किया जाए । सरकार इस तरफ स्वयं पहल करे और जो संचालक हैं यदि उनमें क्षमता है तो उनको मौका दिया जाए काम करने का और यदि वह क्षम्य नहीं हैं तो दूसरे नये संचालक लाए जाएं और उनको मौका दिया जाए और इन उद्योगों को पुनः खड़ा किया जाए । मैं समझता हूं कि इससे देश के उद्योग जो रुग्ण अवस्था में पड़े हुए हैं विकास हो सकता है ।

मेरा सातवां सुझाव है आर्थिक सहयोग के लिए । बहुत से माननीय सदस्यों ने इस हाउस में कहा है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वित्तीय संस्थाएं हैं उन से समय पर यथेष्ट रुपया प्राप्त नहीं होता, इसकी आलोचना समय-समय पर होती है । मैं समझता हूं कि यह नितांत आवश्यक है कि उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय संस्थाएं समय पर यथोचित आवश्यक राशि का प्रावधान करें और उसके संरक्षण और देखभाल की भी सक्रिय रूप से जिम्मेदारी लें जिससे कि जिन संस्थाओं में सरकारी क्षेत्र से रुपया निवेश होता है उसका ठीक से उपयोग होता है, प्रतिपालन होता है, कार्यान्वयन होता है, इसको देखना उनका कर्त्तव्य है ।

मेरा आठवां सुझाव है कि जो भी आर्थिक दृष्टि से उद्योग को देखते हैं, हमारे जो आर्थिक व्यवस्था है, वह मंहगी होती जा रही है । मंहगाई पर चर्चा चारों तरफ होती है ।

मंत्री महोदय, यह नितान्त आवश्यक है कि जो हमारे उद्योग हैं–(समय की घंटी)–हम अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हैं, इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि उद्योग के लागत मूल्य को कम से कम रख सकें, इसके लिए आवश्यक होगा कि सभी मदों में कम से कम खर्चा हो, इसका प्रयास करें ।

हमारा नवां सुझाव सार्वजनिक क्षेत्र से सम्बन्धित है । सार्वजनिक क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे आर्थिक ढांचे में जिसमें लगभग तीस हजार करोड़ रुपये लगे हुए हैं । हम यह देखते हैं कि इसमें से कुछ संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सराहनीय कार्य कर रही हैं, बहुत सी दूसरी हैं जिनके कार्य-प्रणाली में कमी है, उनका उत्पादन अधिक नहीं है, घाटे होते हैं ।

बहुत पहले अपने वित्तीय चर्चा में श्री टी०टी० कृष्णामाचारी 1966-65 में कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों का भी दायित्व है कि वह उचित मुनाफा करें । अभी-अभी 23 अप्रैल, 1984 को वित्त मंत्री, श्री प्रणब कुमार मुखर्जी ने लोक सभा में कहा था कि तीस हजार करोड़ रुपये जो इसमें

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

लगे हुए हैं, यदि उससे हमें दस प्रतिशत भी लाभ मिले, तो हमारे जो घाटे हैं बजट के, वह पूरे हो जायेंगे ।

हमारी माननीया प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस ओर हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया है कि जो इस क्षेत्र में सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, उनका कर्तव्य है कि उत्पादन बढ़ावें और अपने लाभांश को भी बढ़ावें । हम समझते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो कारखाने हैं, वे अपने दायित्व को समझेंगे और अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा करके, अपने मुनाफे को बढ़ा करके जो उनका लाभांश मिलना चाहिए, वह देने में सक्रिय होंगे ।.. (समय की घंटी)

मान्यवर, मेरा दसवां सुझाव निजी क्षेत्र का—निजी क्षेत्र का दायित्व हमारी जो आर्थिक प्रणाली है, उसमें उसका महत्वपूर्ण स्थान है ।

यह नितान्त आवश्यक है कि उनकी तरफ सरकार की उदार नीति अवश्य हो, उनको काम करने की सुविधा दी जाए, लेकिन उनका भी कर्त्तव्य है कि राष्ट्रीय हित में वह अपना उत्पादन बढ़ायें, कम से कम लागत में अधिक से अधिक अच्छा काम करके दिखावें और सरकार के साथ राष्ट्रीय नीति में उनका तालतेल हो ।

मेरा ग्यारहवां सुझाव खादी ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग द्वारा रोजगार प्रावधान का है । हम जानते हैं कि बेरोजगारी की समस्या देश में सब से बड़ी है । बड़े उद्योग और मध्यम उद्योग में रोजगार के लिए संभावना सीमित है—लेकिन जो छोटे उद्योग हैं, उसके जरिए, जो बीस-सूत्री कार्यक्रम हैं, उनके जरिए और खास तौर से खादी और ग्रामोद्योग के जरिए बहुत से रोजगार दिये जा सकते हैं । इसमें सराहनीय कार्य किया जा रहा है । पिछले साल 1983-84 में खादी ग्रामोद्योग का उत्पादन 863 करोड़ रुपये का था जो कि पिछले साल के 764 करोड़ से ज्यादा थी और रोजगार की दृष्टि से 34 लाख 34 हजार की जगह पर 36 लाख 85 हजार लोगों को रोजगार का प्रावधान किया गया है ।

माननीय मंत्री जी, आपको स्वयं ही खादी और ग्रामोद्योग के काम में बहुत रुचि है और आपका इससे बहुत सम्पर्क है और जानकारी है । हम आशा करते हैं—महात्मा गांधी जी ने अपने सार्वजनिक भाषण में जो कहा था कि खादी और ग्रामोद्योग से बढ़ कर कोई उनकी दृष्टि में रोजगार के दूसरे साधन खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हैं—मैं समझता हूं कि उसे ध्यान में रख कर आज गांव में जो इतनी बड़ी बेरोजगारी हो रही है, उसको दूर करने के लिए हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए-(समय की घंटी)-और यह केवल हमारा रोजगार के प्रावधान का सवाल नहीं है, इसका संबंध हमारे सामाजिक ढांचे से, हमारी पारिवारिक स्थिति से, हमारे सांस्कृतिक जीवन से भी इसका संबंध है ।

मैं आशा करता हूं कि कि वह इसको करेंगे ।

अंत में मैं अपना बारहवां सुझाव मंत्री महोदय को देना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर है और वह यह है कि राष्ट्रीय नीति ऐसी हो कि जिससे सारे देश का समीकृत विकास हो । बहुत चर्चा इस सम्बन्ध में इस सदन में और दूसरे सदन में भी हुई है और आज भी कुछ सदस्यों ने इस पर प्रकाश डाला । यदि हम समेकित विकास की दृष्टि से अपने दृष्टिकोण को देखें तो हमें पता लगेगा कि कोई प्रान्त या कसी

प्रान्त के कोई जिले या किसी विशेष क्षेत्र में यदि सुविधाएं नहीं प्रदान की गयी हैं, देश के आजाद होने के 35 साल के बाद भी यदि वहां कोई रोजगार मुहैया करने के साधन उद्योग के द्वारा सुलभ नहीं कराये गये हैं तो क्या यह राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं है कि हम उन क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयास करें ? हम मे से जो लोग ऐसे सुदूर क्षेत्रों में, जिलों में जाते हैं, वहां रहते हैं उन को पता है कि वहां के लोगों की कैसी दयनीय स्थिति है, कितने द्रवित हो जाते हैं हम उन को देख कर । इस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार की ओर से जो पहल की गयी है वह बहुत ही सराहनीय है । यह जो कहा जाता है कि यह नयी नीति ला दी गयी है, ऐसी बात नहीं । जो हमारी आधारभूत नीति अविकसित क्षेत्रों का विकास करने की, पिछड़े लोगों का विकास करने की है उसी का यह एक अंग है । शिव-रमण समिति के सुझाव पर अन्तिम निर्णय की अपेक्षा में कुछ पहले किया गया है वह इस सन्दर्भ में तीन प्रकार के जिले चुने गये हैं : 'ए' प्रकार के जिले जिन में 131 उद्योगरहित हैं जिन्हें केन्द्रीय सहायता 25 प्रतिशत 25 लाख सीमा तक 'बी' प्रकार के 55 जिले जिन में 15 प्रतिशत और जिनकी सीमा 15 लाख रखी गयी है—तीसरे 'सी' ऐसे 114 जिले हैं जिनमें 10 प्रतिशत और 10 लाख की सीमा है—ऐसे 113-114 जिले हैं ।

इस के अतिरिक्त कुछ जो आधारभूत उद्योग सहयोगी उद्योग को 'बी' 'सी' प्रकार के जिलो में निर्धारित सहायता करेंगे उस के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त छूट है। कुछ उस में कम्पनी निवेश के लिए 372(1) धारा के अन्तर्गत 10 से 30 प्रतिशत की छूट दी गयी है । उस में कुछ और भी सुविधाएं प्रदान की गयी हैं । जो बड़े घराने हैं उन को उद्योग रहित जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए राहत दी गयी है । हमे लगता है कि इन सारी छूटों के बावजूद जो सफलता मिली है वह सामान्य ही है क्यों कि बहुत से लोग यह नहीं समझते कि जो हमें सुविधाएं मिली हैं वह यथेष्ट नहीं है ऐसे अविकसित क्षेत्र के लिए । 1982 में 583 लाइसेंस मिले थे जिस में से 145 उस क्षेत्र के लिए मिले, जो 24.9 प्रतिशत ही है । 1983 में 649 लाइसेंसों में 147 मिले जो साढ़े 22 प्रतिशत ही है । 1984 में 147 में 58 उस क्षेत्र के लिए मिले । मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या यह राष्ट्रीय कर्त्तव्य नहीं है, क्या विकसित प्रांतों का यह दायित्व नहीं है कि जो क्षेत्र अविकसित हैं, जो जिले अविकसित हैं उन का विकास हम करें ? क्या अभी तक 25-30 सालों में केन्द्रीय सरकार की सहायता से, राज्य सरकार की सहायता से जिन राज्यों का, जिन क्षेत्रों का विकास हुआ विशेष सुविधा दे कर क्या उन का कर्त्तव्य नहीं है, दायित्व नहीं है कि जिस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ उस क्षेत्र मे विकास को अपनायें और अपना ही कार्य समझें ? क्या यह राष्ट्रीय कार्य नहीं है हमारी दिशा क्या है ? हम किस तरफ बढ़ रहे हैं ? क्या हम इन क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोगों की उपेक्षा करते जायेंगे ? क्या हम यह नहीं समझते कि सुदूर पूर्वांचल के लोग, हिमालय के क्षेत्र में रहने वाले लोग, छोटा, नागपुर, विन्ध्याचल में रहने वाले लोग दबे रहेंगे ? हम यह समझते हैं कि मंत्री महोदय ने जो काम प्रारम्भ किया है वह पुनीत कार्य है । मेरा निवेदन यह है कि इस कार्य को पूरी तत्परता के साथ बढ़ाया जाय और इस की क्षमता को, इस की सुविधाओं को कुछ और बढ़ाया जाय । जो सुविधा 15 प्रतिशत और 15 लाख मिलती

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

बहुत साल पहले उस को यदि अभी 25 लाख और 25 प्रतिशत किया गया है तो वह बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, उद्योग खड़ा करने में ज्यादा रुपया लगता है । इन शब्दों के साथ मै इस नीति का पूर्ण समर्थन करता हूं और जो कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है उस की सराहना करते हुए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं ।

SHRI JERLIE E. TARIANG (Meghalaya): Mr. Vice-Chairman, while participating in the discussion on the working of the Ministry of Industry, I would like to state that auring the last 3 decades, India has emerged as one of the most industrialised nations in the world. Today, Inaia produces practically all the goods required by this country and it is among the first 10 industrialised nations of the world. This has been possible because of the right policies followed by the Congress Government. Though India has made tremendous progress in the field of industry, science and technology, yet there are places in our country which have still remained backward. One such area is the North-Eastern region of our country, comprising of 5 States and 2 Union Territories. North-Eastern region has remained industrially backwara due *to* various factors, like lack of communicaton, lack of local entrepreneurship etc. Goevrnmemt should pay special attention towards the development of infra-structure in this area.

I am grateful to the Government of ndia which has constituted a Standing Committee for the industrial develop-nent of the North-East. This Com-littee has made a number of useful ecommenoations which should be accepted by the Government and implemented. As I mentioned, one of the nportant bottlenecks is transport com-tunication. In the absence of transmit communication, it is difficult for

e people or the entrepreneurs to get their inputs or sell their products easily. Realising this, the Government of India has allowed transport subsidy of 75 per cent. I woulo. urge upon the Government to raise it to 100 per cent. Again for the purpose of this transport subsidy, Government of India has declared Siliguri as the focal point. This is not enough. I urge upon the Government also to make Patna and Calcutta as the focal points.

Government of India should go extensively towards development of entrepreneurship in the North-Eastern region. For this, Government Agencies and Financial Institutions should organise and conduct training courses. The National Small Industries Corporation should play more dominant role in the North-Eastern region.

Another important problem, as I have already pointed out, is the lack of market for the goods produced in the North-East. I am happy, the Government of India has established the North-Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation. This Agency should be strengthened and similar agencies for non-agricultural products should also be set up. Due to lack of communication and lack of manpower, large industries could not be set up in the North-Eastern region. Emphasis has, therefore to be given towards the development of small and medium scale industries.

Climatically, North-Eastern region is suitable for development of electronic industry. I would urge upon the Government of India and the Department of Electronics to evolve a special scheme and go all out for the development of electronics industry in the North-East.

Mr. Vice-Chairman, "Meghalaya, the State I have the honour to, represent in this august House, has rich mineral deposits. Besides horticulture and forest produce, almost its entire range boraeting Bangladesh has large deposits *of* coal and limestone. It has also a number of rivers, streams and

waterfalls left untapped. I would, therefore, urge upon the Government of India and the Planning Commission to, consider the possibility of setting up mini-hydel projects and mini cement plants and also mini ropeways connecting difficult trains of the area particularly in the State of Meghalaya. This will improve the economic condition of the people in the State of Meghalaya.

With these few words, Sir, I resume my seat. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Mr. Ghulam "Rasool Matto. Your United Associa tion of Parties has already exhausted the time allotted to them. ..

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Thank you very much for accommodating me.

Mr. Vice-Chairman, Sir, although 1 belong to the Opposition Party, I must say that our industrial progress, dur ing the last thirty years has not been as bad as is made out to be. Of course, we had set a target. May be, the target of 8 per cent or 9 per cent growth, which we had set was on the higher side. But in any case, we have achieved progress and many things are being manufactured in our country about which we must be very proud.

But there are two very disturbing aspects about our industries. One is in regard to the public sector. The position at the moment is, we have spent a lot of money, invested a lot of money, in o,ur public sector. But most of the units are not giving the dividends which we expect out of them A few months ago, almost last year we passed in this House, the Electri-city Supply (Amendment) Bill, wherein it has been made incumbent on the electricity boards that they should give a minimum return of three and a halt or four per cent. 1 would urge the hon. Minister *to* consider whether he can have different categories in the public sector. Those industries which are of permanently bad nature can be set apart. In regard to those units which are in a viable state or are not so bad, we should set a minimum target for them, in regard to return on investment. Say, seven per cent return on investment. And what Is important Is—this may be tried, we do this in the private sector—the person in charge of that particular unit should be made responsible and his emoluments, his promotion, his perks etc. should be related to the return which he gives from that particular unit. It this sort of incentive is given, those who are working in the public sector would be able to give better results. This should be tried because the recent trend is not healthy so far as the return on investment from the public sector is concerned.

The second point I have to make in this regard is the sickness in industries. At the moment, what we are doing is, we take over the industries when they are really sick. I had, In one of the earlier Sessions, referred to the Industries (Development ana' Regulation) Act, which is on the statute book. Under section 18 and section 18A of that Act, you can monitor the performance of evory industry which has been registered under the Industries (Development and Regulation) Act. You must have a monitoring cell in your own depart-" ment, so that in regard to every industry which is registered under this Act, you can see what is the performance of that particular industry. As soon as you feel. according to the statistics available with you and according to the monitoring that you do, that a particular industry 1? going to get sick, you can issue directions under section 18AA and take over that industry befare it is completely taken over by the sickness. This is a very important thing. This may please be tried,and this should be done. -

The third point which I want to make is, in reply to a question which I had put to the hon. Industry Minister, in the last Session, it was stated that the investment in the public sector in the entire country is to the order

[Shri Ghulam Rasoul Matto]

of Rs. 26,000 crores, although the recent figure given is Rs. 36,000 crores. In any case I do not know what is being mixed with what, but the figure I have got in reply to my question is Rs. 26,000 crores. And the share of Jammu and Kashmir is 0.06 per cent. I can understand that there are certain locational advantages for certain industries to, be set up in particular areas. For instance if iron ore was available in Bihar, you had to set up iron and steel factory over there. Or oil was to be drilled from Bombay High or Assam, you had to put the oil industry there. But time has now come lor the Industry Minister to rectify this imbalance. If we continue with this edho.cism, and more over if any person has got any pull, he gets that industry set up in his area under the public sector, this trend is going to be sucidal and this imbalance will grow in such a way that at a point of time, this will create a lot of difficulties for the Government. I would therefore request the hon. Minister to react to my proposal that a fresh view has to be taken and guidelines have to be framed for setting up industries in the Public Sector issued. In that context, I have only this submission to make that the Jammu region in Jammu & Kashmir State is as good or as bad as any ether part of the country, where heavy and large scale industries can be set up. So far as Kashmir region is concerned. You can *set* up electronic goods manufacturing factories and other such factories in this part. The Seventh Plan is on the anvil and I would humbly request the hon. Minister that he may take a sympathetic view of Jammu and Kashmir State and try to establish such industries there on a priority basis, so that this imbalance is done away with.

Of course, a lot of things have been done in the small scale industries sector and there has been a perceptible Increase in production and sales in this sector. I must say that although there is a large amount of sickness in the small scale sector, yet the small scale industry Is a sector which gives employment to a lot of people and this sector should be encouraged at all costs. But there are two handicaps with respect to this small scale sector Number one Is the marketing part of it. In many States—I am talking of Jammu and Kashmir State and this is the position with regard to other States also—there is a price preference of 15 per cent fixed as the guidelines by the Centre for purchases by different departments from the small scale sector. That is, if a particular commodity is available for Rs. 100 and if the same thing is available for Rs. 115 In the small scale sector, Government has to purchase it from this sector. The Central Government has to come in a very big way, either directly or through the States, to ensure that this marketing part of the small scale sector is looked after and this price preference is implemented and all the purchases are made from the small scale industries preferably, as provided for in the guidelines.

The second point I have to make is that the cost of even a small machine has gone up very high. So I feel that the limit of Rs. 25 lakhs fixed for small scale industries needs to be increased. 1 would request the Hon. Minister to kindly consider it now because with the building, machinery and other things being so high priced, Rs. 25 lakhs is a very small amount and this needs to be looked into so that more people can get benefit out of thi9.

With regard to modernisation, it *is of* paramount importance in the industrial sector and can assist to a large extent in removing sickness in the different sectors of the industry. I have only to submit that the Industry Ministry is not perhaps asserting it self in the way it has to. With the new Budget that has come, you will be surprised to know, Mr. Minister, that the incidence of custom duty auxiliary Custom duty and other duties put together conies to 80 per cent on import of Machinery. No country in the world has imposed such

a high , duty on the import of machinery. Any machinery which can be imported from outside will be only that which is not available in the country but to impose 80 per cert duty on this is counter-productive and also retards modernisation process. I kwould request the hon. Minister take this matter with the Finance Mlnls-t and ensure that, In the first instance, the duty is done away with and if that is not possible, it should be slashed to, such an extent that It is possible for people to import of it.. *(Time bell rings).*

Sir, you have been ringing the bell very often. I think I have twelve points more.

THE VICE-CHAIRMAN- (SHPI R. RAMAKRISHNAN): You have spoken for twelve minutes.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: All right, Sir, I have very many points and I think I will have occasions to speak on them. I thank yon very much for giving me this time.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): Sir, I am very glad to speak on the Industry Ministry, Sir. Mahatma Gandhi, the Father of the Nation said once, "Uf God gives me rebirth he must give it to me in the form of bread." Again he , said while leading to freedom move-1 merit of this country. *"Charkha Chala ' chalakar lenge Swaraj"* That means, when he spoke about bread, he meant agriculture. And when he said, *"Charkha chala chalakar"* he was speaking for industries. So, the Father of the Nation, at the time of leading the freedom movement of this country, had two things in his mind. One was about agriculture and the other was about industry.

I am very proud to speak in this august House and say that under the able and eminent leadership of the great Father of our Nation. Pandit Jawaharlal Nehru brought out the modern temples of India in the form of industries in this country. He looked towards agriculture and there Is a lot of development and advancement in agriculture and agricultural technology.

Pandit- Jawaharlal Nehru said that today's industries are the modern temples of India. He created the scientific base of industries by the formulation of the National Physical Laboratory, the National Chemical Laboratory and so many other national laboratories. He constructed new dams like Bhakra Nangal and others.

While coming to the subject, I would like to state that so many speakers spoke on it but I think most of them did not come to the subject at all-They spoke vaguely. When I come *to* the subject actual, that is inaustry, India has emerged as one of the most important and ordered industrial coun-• tries in the world. That data T have. So, from that point of view I would like to make some important points.

The first important industry of India is the small-scale industry. We are having two types of industries—small scale industry and heavy industry-There are other industries which do not come under the purview of the Industries Department, like electricity petroleum and so many other things. To speak about small-scale industries, the small-scale industries are very important from the following main objectives:—

1. Wider decentralisation of the industries.

2. Utilisation of the scattered re sources in terms of men, material as well as money.

3. Revival of the traditional indus tries as well as the creation of classes of entrepreneurs.

Sir, what was the outlay in the First Plan? It was only Rs. 30 crores. Now, what was the outlay in the Sixth Plan? It Is 1,780 crores—an outlay, which is a fantastic achievement we have made through our Plans. Pandit Nehru said that unless there Is planning nobody can prosper. So we formulated cur six Plans and now we are on the verge of formulation of the Seventh Plan. So, Sir, if we compare the figure of 1950-51 with the figure of 1983-84, the Iat*e»

[Shri Vithal rao Madhavrao Jadhav]

figure is sixty times more at the current prices. Unregistered manufacturing units increased from Rs. 785 crorea in 1960-61 to Rs. 4,632 crores in 1977-78. The value added is 51 per cent more. During the Sixth Plan period, from 1980 to 1985...the output is just Rs. 15,725 crores in the terminal year 1984-85. It has been envisaged that the corresponding rate of growth will be 8 per cent per annum. The employment coverage, both full time and part time, is estimated to increase from 23.58 million persons in 1979-80 to about 32.60 million persons in 1984-85. Sir, the financial assistance by the commercial banks increased from Rs. 211 crores at the end of 1968, before the nationalization, to about Rs. 2,844 •crores in 1980. I am talking of the small scale sector. In 1980, it is 12 times more than what it was in 1968. The share of the small scale industries has increased from Rs. 251.07 cores in June, 1969 to Rs. 3,763.82 crops' at the end of 1981, which is 15 times more than what it was in 1969. The National Bank for Agricultural and Rural Development. ..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R." RAMAKRISHNAN): Mr. Jadhav would yctu like to continue tomorrow

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV; Yes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at two minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 9th May, 1984.